RNI. NO. RAJHIN/2021/82156

डाक पंजीयन संख्याः RJ/ALW/866/2023

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा

जज्बा सच दिखाने का

वर्ष -06 | अंक -152 | मूल्यः 2.00 रू. | अलवर, गुरूवार 13 अगस्त 2026 | प्रभात संस्करण | कुल पेज- 8

WWW.Voiceofpratigya.com | Twitter.com/Voiceofpratigya | facebook.com/Voiceofpratigya | YouTube.com/Voiceofpratigya | Instagram- Instagram.com/Voiceofpratigya | 9414508610 | pratigya.alwar@gmail.com

जेपीसी के पास भेजा गया एफसीआरए संशोधन विधेयक, समिति में 21 सदस्य लोकसभा और 10 राज्यसभा के होंगे

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

एफसीआरए संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की सहमति बन गई है। बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया, जो पारित हो गया। प्रस्तावित जेपीसी (जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी) में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे।

जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र तक देगी अपनी रिपोर्ट

प्रस्ताव में कहा गया कि विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा जाए, जिसमें लोकसभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत इस सदन के 21 सदस्य और राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होंगे। समिति को विधायी प्रावधानों की गहन जांच करने का काम सौंपा गया है और समिति को 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

विपक्ष की मांग- बिल वापस ले सरकार

हालांकि, विपक्ष ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा, 'सरकार अल्पसंख्यकों और एनजीओ को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। हमारी मांग है कि सरकार इस बिल को वापस ले।' विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'केसी वेणुगोपाल ने गलत बोला है। कई दिनों से कांग्रेस और अन्य दलों ने मांग की कि एफसीआरए संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेजा जाए। जब इस महत्वपूर्ण बिल को जेपीसी में भेज रहे हैं तो विपक्ष

अखिलेश यादव का सरकार पर हमला

समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी एफसीआरए संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा, 'सरकार जो एफसीआरए ला रही है, इसके खिलाफ पूरा विपक्ष है। मंत्री (किरेन रिजिजू) ने बोला कि विधेयक अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ नहीं है। मंत्री बताएं कि आज तक सरकार जो बिल लाई है, बिना अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ वे कौन सा बिल लेकर आए?'

अखिलेश के आरोपों का रिजिजू ने क्या दिया जवाब?

इस पर जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा, 'मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ है।' अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए रिजिजू ने कहा, 'देश में झूठ फैलाया जा रहा है। किसी अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप (विपक्ष) चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में लाकर खर्चा किया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है।' इसके बाद लोकसभा ने 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव पास किया।

को इस पर आपत्ति हो रही है।' रिजिजू ने कहा कि केसी वेणुगोपाल या अन्य सदस्य को इस बिल में आपत्तिजनक कुछ बिंदु लगते हैं तो जेपीसी में मत रख सकते हैं। इसमें उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'इस विधेयक से किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है। पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहे हैं।'

गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा- हम उन्हें सुनना ही नहीं चाहते

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का साफ कहना है कि हम अमित शाह के भाषण को सुनना ही नहीं चाहते। मेरा 'हम' से मतलब देश की युवा पीढ़ी से है। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह में हिम्मत ही नहीं है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

बुधवार को संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'हम बस जानना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां किसने चलवाईं? किसने इसके आदेश दिए? लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए? वो आदेश गृह मंत्रालय से दिए गए। क्या अमित शाह ने आदेश दिए या नहीं। अगर उन्होने इसके आदेश दिए तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वे दोषी हैं और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिए तो भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वे पद के योग्य नहीं हैं।' राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह 20 दिनों से संसद में नहीं आ रहे हैं। वे गाड़ियों के काफिले के साथ संसद आते हैं। उनके घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं कि कहीं कोई छात्र न आ जाए। गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है।

जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, तभी एक पत्रकार ने बीच में ही सवाल कर दिया, जिससे राहुल गांधी नाराज हो गए और पत्रकार से कहा कि 'आप सत्ता पक्ष के लोगों को भी क्या इसी तरह से बीच में टोकते हैं? हमें 24 घंटा टोकते रहते हैं, लेकिन उन्हें टोकने की आपकी हिम्मत नहीं है। क्यों आप उनके सामने चुप करके खड़े हो जाते हैं? पूरे देश के छात्र सरकार से नहीं डर रहे हैं तो आपको भी नहीं डरना चाहिए।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद परिसर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, सबसे पहले 'लापता' और 'भाग गए' जैसे शब्द अब भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में लगातार सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सत्र शुरू होने के बाद से लगातार संसद आ रहा हूं। मैं अपने कक्ष में बैठता हूं। लेकिन विपक्ष दोनों सदनों में संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। ऐसे में कोई क्या कर सकता है? अमित शाह ने कहा, 'मैं तीन बजे विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दूंगा। मैं आज तीन बजे से कल तीन बजे तक भी बैठने के लिए तैयार हूं। मैं विपक्ष के हर सवाल का जवाब दूंगा और सच सामने आएगा। अब ये विपक्ष को तय करना है कि वे बातचीत करना चाहते हैं या फिर हंगामा।'

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ससंद में विपक्ष के सवालों से बच रहे हैं। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि संसद में बहुमत होने के बावजूद गृह मंत्री सवालों से बच रहे हैं। टीएमसी सांसद ने कहा, पार्टियों को तोड़ने और बहुमत होने के बावजूद, उनका सदन से दूर रहना दर्शाता है कि वे विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं और अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं। वे आंतरिक रूप से जानते हैं कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, उनके निर्देशों पर लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई गलत थी, उनके पास कोई जवाब नहीं है।'

विपक्ष के विरोध पर गृह मंत्री शाह की दो टूक- मैं आज तीन बजे विरोधियों के सभी सवालों का जवाब दूंगा

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

संसद के मानसून सत्र का आज 18वां दिन है। विपक्ष कई दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में पुलिस की कथित ज्यादती अन्य मुद्दों पर जवाब की मांग कर रहा है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री ने गुरुवार को कहा कि वह कल दोपहर तीन बजे तक सभी सवालों का जवाब देंगे। विपक्ष के विरोध पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा, सभी लोग अपने सवाल लिखकर दें। मैं कल तीन बजे सभी सवालों का जवाब दूंगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सबसे पहले 'लापता' और 'भाग गए' जैसे शब्द अब भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में लगातार सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सत्र शुरू होने के बाद से लगातार संसद आ रहा हूं। मैं अपने कक्ष में बैठता हूं। लेकिन विपक्ष दोनों सदनों में संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। ऐसे में कोई क्या कर सकता है? चर्चा को लेकर शाह ने कहा कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि सरकार नीट परीक्षाओं के विरोध को लेकर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हमने चर्चा के लिए समय तय करने और विपक्ष के तैयार रहने की बात कही थी। यह उनकी शुरुआती मांग थी और हमने इसे मान लिया था। शाह ने कहा, मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वे चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कहा, अब जनता तय करे कि भाग कौन रहा है।

शाह ने विपक्ष से कहा कि वह आज दोपहर तीन बजे तक लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र दे। उन्होंने कहा कि सरकार आज दोपहर तीन बजे से कल दोपहर तीन बजे तक हर पहलू पर चर्चा के लिए तैयार है। शाह ने कहा, मैं सदन में बैठूंगा। मैं सभी की बात सुनूंगा और हर मुद्दे का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा, मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि वे चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते थे। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ संसद की कार्यवाही चलने देनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष ने साफ कहा है कि हमें अमित शाह का भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं 'हम' कहता हूं, तो मेरा मतलब इस देश की युवा पीढ़ी से है। उन्होंने कहा, छात्रों पर गोली किसने चलाई? छात्रों को कीलों वाली लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था? अगर उन्होंने ऐसा आदेश दिया था, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, पिछले 20 दिनों से अमित शाह 'लापता' हैं। भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है। वह सदन में नहीं आ सकते।

वहीं, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, जहां-जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां भ्रष्टाचार आम बात बन गया है। चाहे वह तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या झारखंड। तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। लेकिन कितनी सीटें होंगी और परिसीमन किस तरह किया जाएगा, यह फैसला संसद को करना है।

'क्या हम चुपचाप बैठे रहें', मीडिया के सवाल पर बिफरीं प्रियंका? गृह मंत्री पर साधा निशाना

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को एक बार फिर जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार से जवाब मांगे। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब युवा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाते हैं तो उनके साथ होने वाले व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है? दरअसल बुधवार को जब प्रियंका गांधी संसद भवन परिसर पहुंची तो उन्हें कई मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। इस दौरान पत्रकारों ने संसद में जारी गतिरोध पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया मांगी। इस पर प्रियंका गांधी नाराज हो गईं और पूछा कि 'आप क्या चाहते हैं? जब हजारों छात्र इकट्ठा होते हैं और उनकी एक ही मांग होती है तो आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग किया जाता है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार में एके 47 चलाई जाती है और हम सरकार से सवाल भी न करें। हम भी चुपचाप बैठे रहें, जैसे आप लोग चुप हैं?

प्रियंका गांधी ने लोकतांत्रिक जवाबदेही का मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या गृह मंत्री अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेय मानते हैं या नहीं? उन्होंने कहा, 'क्या आप जनता के प्रति जवाबदेय नहीं हैं? इसलिए हमें भी शांत बैठना चाहिए?' प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष चुप नहीं रहेगा। विपक्ष प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस बल के इस्तेमाल के मुद्दे पर गृह मंत्री से संसद में जवाब देने की मांग कर रहा है और साथ ही माफी मांगने की भी मांग कर रही है। इस मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र बाधित रहा है। अब सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है और गृह मंत्री संसद में इस पर जवाब देंगे। अब वहीं एनडीए सांसदों ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठा दिया है।

जस्टिस वर्मा के विरुद्ध अब दर्ज हो सकती है एफआईआर, कानूनी विशेषज्ञों का बड़ा दावा

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

कानूनी विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध अब एफआईआर दर्ज की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने उन्हें सरकारी आवास पर नकदी मिलने के आरोपों का दोषी पाया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि महाभियोग की प्रक्रिया स्वतः खत्म हो गई है क्योंकि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ राकेश द्विवेदी ने कहा कि अगर कोई नया कदम उठाया जाता है तो जस्टिस वर्मा के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'अब रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है और वह पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा सकता। इसलिए महाभियोग प्रस्ताव स्वतः खत्म हो गया है। मेरी राय में यह बेअसर हो गया है, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर एफआइआर निश्चित रूप से दर्ज की जा सकती है। ' वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि चूंकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए उनकी राय में जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'इस्तीफे की स्थिति में उन्हें पेंशन पाने का अधिकार होगा। लेकिन अगर उन पर महाभियोग चलाया जाता है, तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात अगर जांच समिति ने कहा है कि एफआइआर दर्ज की जानी चाहिए, तो एफआइआर दर्ज की जानी चाहिए। 'जाने-माने संवैधानिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि महाभियोग का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने कहा, 'मेरी राय में संसद का अधिकार क्षेत्र अब खत्म हो गया है।

'कल कुछ नहीं होगा': खरगे ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर शाह से मांगा जवाब

कहा- संसद में जारी रहेगा विरोध

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में अपना रुख बनाए रखेगा। पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा, 'कल कुछ नहीं होगा। हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं।' आज विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और 'अमित शाह जवाब दो' के नारे लगाए। विपक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी और अन्य राज्यों में छात्रों के खिलाफ पुलिस की ओर से बल प्रयोग किए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। एफसीआरए बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की मांग पर खरगे ने कहा, 'इसे भेजा जाना चाहिए।' एफसीआरए देश में व्यक्तियों, संघों और संगठनों की ओर से विदेशी योगदान लेने और उसके इस्तेमाल को रेगुलेट करता है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि ऐसे योगदान का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए हो, जिसके लिए वे मिले हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 को 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और अभी संसद में इस पर विचार चल रहा है। संशोधित एफसीआरए नियम, 2026 को 22 जून को नोटिफाई किया गया था और ये लागू हैं। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शाह पर तीखा हमला किया। उन्होंने देश भर में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठी और पैलेट गन समेत बल के कथित इस्तेमाल के लिए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, 'आपको क्या लगता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब हजारों छात्र इकट्ठा होते हैं और उनकी एक ही मांग होती है

अलवर में सत्ता का तमाशा: मंत्री खुद धरने पर, नौकरशाही राजा-प्रजा खेलती रही और पांच कागजों से 'न्याय' का नाटक

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

अलवर नगर निगम का बुधवार का दिन देखकर लगता था जैसे कोई राजनीतिक कॉमेडी शो चल रहा हो। 2012-13 की सफाई कर्मचारी भर्ती के 329 चयनित अभ्यर्थियों को 14 साल बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हाईकोर्ट का फैसला, डीएलबी के निर्देश, बार-बार के पत्राचार–सब कुछ कागजों की धूल में दब गया। नतीजा? वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा खुद सफाई कर्मचारियों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर लगभग पांच घंटे धरने पर बैठ गए। अपनी ही सरकार के प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ! यह दृश्य देखकर विपक्ष हंस रहा था, आम आदमी सिर पकड़ रहा था और नौकरशाही शायद चाय की चुस्की ले रही थी। सत्ता पक्ष का मंत्री धरने पर बैठा हो और अफसर अपने कमरों में आराम से फाइलें पलट रहे हों–यह तस्वीर राजस्थान की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की हकीकत बयान कर रही थी।

संख्या का जादू: 329 से 69 फिर सिर्फ पांच

मामला पुराना है। 2012 में भर्ती हुई , लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिले। अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए। 2019 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। डीएलबी की समिति 2023 तक सोई रही। भाजपा सरकार आने के बाद डीएलबी ने 2025 में निगम को निर्देश दिए। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने जादू दिखाना शुरू कर दिया–पहले 100 पात्र बताए, फिर 87, फिर 69। आखिरकार पांच कागजों से काम चला लिया गया। मंगलवार को आयुक्त सोहन सिंह नरूका का तबादला हुआ, जिसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा और भड़का। मंत्री खुद मान चुके थे कि उन्हें छह-सात महीने से गुमराह किया जा रहा था। संख्या घटाने का यह खेल देखकर लगता था कि फाइलें नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों के हक की हत्या हो रही है।

मंत्री का धरना और कलेक्टर पर सबसे गंभीर आरोप

बुधवार को मंत्री शर्मा सफाई कर्मचारियों के साथ निगम पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कलेक्टर आर्तिका शुक्ला पर खुलकर हमला

बोला–

'उसको तो समाज का भला करना नहीं है, उसको तो लूटकर खाना है कलेक्टर बनकर यहां पर। हरामखोरी कर रखी है।'

उन्होंने आयुक्त से भी पूछा– 'सीनियर आईएएस रवि जैन की तुम नहीं मान रहे, प्रतीक जुईकर की तुम नहीं मान रहे। कलेक्टर और आयुक्त, आप लोग चाहते क्या हो इस शहर से? तुम कोई राज्य सरकार से बड़े हो गए क्या या तुम ही सरकार हो? '

कलेक्टर ने मंत्री से कहा कि नियुक्ति पत्र जारी करने वाला नियोक्ता जिला प्रशासन नहीं है। मंत्री ने चेतावनी दी कि जब तक आज ही नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते, वे धरना नहीं छोड़ेंगे। यह दृश्य देखकर लगता था कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि अफसरों के आगे नतमस्तक हो चुके हैं।

बाहर मंत्री का धरना, अंदर कांग्रेस का कब्जा और भिड़ंत

बाहर मंत्री धरने पर बैठे रहे, अंदर आयुक्त के चैंबर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता घुस गए। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की हो गई। कांग्रेस ने पूर्व पार्षद जितेंद्र सैनी पर धक्का-मुक्की का आरोप लगाया। पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा। पूरा निगम परिसर राजनीतिक अखाड़े में बदल गया। एक तरफ सफाईकर्मियों का दर्द, दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष की कुश्ती–यह दृश्य प्रशासनिक विफलता से ज्यादा राजनीतिक तमाशा लग रहा था।

पांच घंटे बाद पांच पत्र और 16 अगस्त का आश्वासन

लगभग पांच घंटे के गतिरोध के बाद एडीएम योगेश डागुर और आयुक्त नरूका पांच नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचे। मंत्री ने उन्हें सफाई कर्मचारी नेता को सौंपा। धरना खत्म। बाकी पात्र अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अलवर सभा में नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया गया। तीन सदस्यीय टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। यानी 14 साल बाद भी जांच जारी है। पांच पत्र देकर धरना तो खत्म कर दिया गया, लेकिन बाकी 324 के लिए फिर से इंतजार का चक्र शुरू हो गया।

विपक्ष का तंज और सत्ता की शर्मिंदगी

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने तंज कसा–जब सत्ता पक्ष का मंत्री ही सड़क पर बैठने को मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है। जूली ने कहा कि मंत्री नाम के हैं, फैसले अफसर करते हैं। डोटासरा ने कहा कि मंत्री का ब्यूरोक्रेसी पर भ्रष्टाचार का आरोप सरकार की अराजकता दर्शाता है। सचिन पायलट ने भी सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। विपक्ष को इससे बेहतर मौका और क्या चाहिए था?

नौकरशाही की जीत, मंत्री की मजबूरी

यह पूरी घटना नौकरशाही की ताकत और राजनीतिक कमजोरी का जीता-जागता उदाहरण है। मंत्री खुद पांच घंटे धरना दें, कलेक्टर पर 'लूटकर खाने' का आरोप लगाएं, आयुक्त को घर से बुलाकर फटकार लगाएं–फिर भी सिर्फ पांच पत्र मिलें। बाकी के लिए 16 अगस्त और अमित शाह की सभा का इंतजार। डीएलबी ने 329 को पात्र माना, लेकिन स्थानीय स्तर पर संख्या घटती गई। मंत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें छह-सात महीने से गुमराह किया जा रहा था। सवाल यह है कि अगर मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी?

सफाईकर्मियों की अधूरी खुशी और असली सवाल

सफाई कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी जरूर दिखी, लेकिन वह खुशी कितनी स्थायी होगी, यह समय बताएगा। 2012 से चली आ रही भर्ती, कोर्ट के चक्कर, सरकारें बदलना, पत्राचार का खेल–सब कुछ एक ही बात बताता है: गरीब सफाईकर्मी का हक अफसरों की मेज पर धूल खाता रहता है। मंत्री धरना देकर अपना राजनीतिक अंक तो बना लें, लेकिन व्यवस्था वही रहती है। जहां चुना हुआ प्रतिनिधि अफसरों के आगे मजबूर हो, वहां आम आदमी का क्या भरोसा?

पांच कागजों से न्याय का तमाशा

अंत में पांच नियुक्ति पत्रों से मामला 'शांत' हो गया। शेष 324 के लिए आश्वासन। जांच टीम सक्रिय। लेकिन सवाल बाकी हैं–क्या 16 अगस्त को वाकई पत्र मिलेंगे? क्या दस्तावेजों की जांच में फिर संख्या घटेगी? क्या नौकरशाही फिर से 'मार्गदर्शन' मांगेगी? अलवर का यह तमाशा सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की नाकामी का प्रतीक है। जहां मंत्री धरना दें और अफसर मुस्कुराएं, वहां लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाता है। सफाई कर्मचारियों का हक 14 साल बाद भी अधूरा है। पांच कागजों से न्याय का नाटक तो हो गया, असली न्याय अभी दूर है।

पीएनबी आरसेटी में एडवांस कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रशिक्षण शुरू

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (पीएनबी आरसेटी) में एडवांस कंप्यूटर अकाउंटिंग के 38 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में जिला अग्रणी प्रबंधक राहुल दूल और सीनियर मैनेजर जावेद खान मौजूद रहे। राहुल दूल ने कहा कि वर्तमान समय में लेखांकन और डिजिटल अकाउंटिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं को इस क्षेत्र में तकनीकी और व्यावहारिक कौशल हासिल कर रोजगार व स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। संस्था निदेशक जे.पी. मीणा ने प्रशिक्षणार्थियों से नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहकर प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। संकाय सदस्य जयप्रकाश सिंघल ने बताया कि प्रशिक्षण में बुककीपिंग, अकाउंटिंग और संबंधित व्यावहारिक विषयों की जानकारी दी जाएगी। 38 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को आवास और भोजन की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में प्रशिक्षक रामलाल सुरेला, कार्यालय सहायक हिमांशी शर्मा और अटेंडर राहुल अठवाल मौजूद रहे।

प्रधान पब्लिक स्कूल में योग को बताया जीवन दर्शन, नियमित अभ्यास पर जोर

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा लक्ष्मणगढ़

श्री गोविंद देव परोपकारी ट्रस्ट के तत्वावधान में मंगलवार को प्रधान पब्लिक स्कूल पिनान में योग सत्र आयोजित किया गया। पतंजलि योगपीठ के योगाचार्य केदार नाथ शर्मा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को योगाभ्यास कराया तथा योग के विभिन्न आयामों और जीवन में इसके महत्व की जानकारी दी। योगाचार्य ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन दर्शन, आत्मानुशासन और संतुलित जीवन की पद्धति है। नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ अपने व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास कर सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग सत्र में विद्यार्थियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। केदार नाथ शर्मा ने कहा कि योग को केवल वैकल्पिक चिकित्सा या व्यायाम तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य व्यक्ति को भीतर से स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक बनाना है। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वार्थ, आग्रह और अहंकार से ऊपर उठकर योग को समग्र विज्ञान के रूप में समझने की बात कही। सत्र के दौरान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अवधारणाओं के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे वैज्ञानिक उदाहरणों के माध्यम से विषय को समझाया गया। योग की पारंपरिक मान्यताओं और प्राणायाम के महत्व पर भी जानकारी दी गई। विद्यालय की प्रधानाध्यापक रजनी ने बताया कि विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय निदेशक शशिकांत, रजनी सहित रामानंद, सुमित, श्याम सुंदर, दिनेश, पूजा, लक्ष्मी, राजवती, आंचल आदि शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 के न्यायाधीश बी.एस. पांडिया ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख रुपए दिलाए जाने की भी अनुशंसा की है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता की मां ने 10 जून 2025 को बड़ौदामेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 9 जून की रात करीब 2 बजे आरोपी राकेश नाबालिग को कथित तौर पर जबरन ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी रोती हुई घर के पास रास्ते में मिली। परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों के बयान और 21 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश बी.एस. पांडिया ने आदेश में कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म का उसके मन और मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर के सचिव को अनुशंसा भी भेजी है।

थानागाजी में जमीन रजिस्ट्री धोखाधड़ी मामला गरमाया, सैकड़ों ग्रामीणों का धरना

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा थानागाजी

बैंक से लोन दिलाने के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराने के आरोपों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित किशन लाल सैनी उर्फ गदया के समर्थन में बुधवार को सर्व समाज के सैकड़ों ग्रामीण भाजपा नेता रोहिताश घांघल के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की।

धरने से पहले शिव बगीची में सर्व समाज की बैठक हुई, जिसमें मामले को लेकर चर्चा के बाद उपखंड कार्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद कस्बे और आसपास की ढाणियों से आए महिला-पुरुष पैदल उपखंड कार्यालय पहुंचे। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक इंदु लोधी और थानाधिकारी महावीर देबाना भी मौके पर पहुंचे।

ग्रामीणों ने उपखंडाधिकारी सविता शर्मा को मांग पत्र सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की। उपखंडाधिकारी के पूर्व में दर्ज प्राथमिकी पर लगी एफआर को वापस खुलवाकर जल्द कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया।

भाजपा नेता रोहिताश घांघल ने कहा कि पीड़ित को न्याय मिलने तक मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराने की मांग की।

ग्रामीणों का आरोप है कि लाला की ढाणी निवासी किशन लाल सैनी की जमीन आरोपी महेश उर्फ पटवारी ने बैंक से लोन दिलाने के नाम पर अपनी पत्नी दीपमाला के नाम रजिस्ट्री करा ली। आरोप है कि रजिस्ट्री के बदले दिया गया बैंक चेक भी पीड़ित के खाते में नहीं पहुंचा। ग्रामीणों के अनुसार पीड़ित अशिक्षित और मानसिक रूप से कमजोर है और उसे गुमराह कर रजिस्ट्री कराई गई।

बताया गया कि मामले में पहले भी पुलिस थाने में शिकायत और धरना दिया गया था। धरने के दौरान अशोक सैनी, रामेश्वर यादव, रामू कबाड़ी, महेंद्र बोहरा, राजेश सैनी, सीताराम, डालचंद सैनी, बाबूलाल सैनी, महेंद्र सैनी और मुकेश सैनी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

नशे के खिलाफ जनजागरूकता और समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के पोस्टर एवं टी-शर्ट का विमोचन किया गया और उपस्थित लोगों को नशामुक्त भारत की शपथ दिलाई गई।

सुधीर चौधरी ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे की रोकथाम पुलिस-प्रशासन के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से खेल, योग और अध्ययन जैसी सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने तथा स्वयं जागरूक रहकर दूसरों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की अपील की।

कार्यशाला में मनोचिकित्सक डॉ. नरेन्द्र कुमार, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर लेखराज अग्रवाल, नागेन्द्र और चेतन सिंह ने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने नशे से बचाव के उपाय भी बताए। अतिथियों ने हस्ताक्षर बोर्ड पर हस्ताक्षर कर नशामुक्त भारत का संदेश दिया।

कार्यक्रम में यूआईटी सचिव धाईगुडे स्नेहल नाना, जिला परिषद सीईओ सालुखे गौरव रवीन्द्र, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर अम्बालाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार, सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा, पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा सहित अधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, एनसीसी, स्काउट और बड़ी संख्या में विद्यार्थी व युवा मौजूद रहे।

जिला ब्लड बैंक में घटते रक्त भंडार को देखते हुए 170 यूनिट रक्तदान

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

जिला ब्लड बैंक में घटते रक्त भंडार को देखते हुए जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विजय सॉल्वेक्स कंपनी के चेयरमैन विजय डाटा और डायरेक्टर सौरभ डाटा की ओर से गंगादान निरंजनलाल डाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर विकास न्यास के उपसचिव जितेंद्र सिंह नरूका ने किया। कार्यक्रम संयोजक एस.के. पाराशर ने बताया कि महावर धर्मशाला, कुश मार्ग पर आयोजित शिविर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रक्तदान किया गया। रक्त संग्रहण का कार्य सेठ माखनलाल महावर चैरिटेबल ब्लड बैंक के डॉ. सुशील कुमार बंसल और राजीव गांधी राजकीय चिकित्सालय की डॉ. दिया जैन के नेतृत्व में हुआ।

शिविर में करीब 170 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान के प्रति लोगों में खासा उत्साह रहा। महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं करीब 42 लोगों ने पहली बार रक्तदान कर इस अभियान में भागीदारी निभाई।

आयोजकों ने बताया कि रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र, गिफ्ट हैम्पर और मेडल देकर सम्मानित किया गया। शिविर के सफल आयोजन में ब्लड बैंक टीम के अलावा डाटा ग्रुप के रामप्रकाश गुप्ता, रामानंद गुप्ता, परिवेश गुप्ता, ताराचंद अवाल, मुकेश शर्मा और जितेंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा।

आयोजकों ने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का श्रेष्ठ माध्यम है। समय पर उपलब्ध रक्त जरूरतमंद मरीज का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोगों को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाना जरूरी है।

जयसिंहपुरा में बोरिंग से 550 फीट केबल चोरी, किसान परेशान

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा थानागाजी

जयसिंहपुरा गांव में अज्ञात चोर किसानों की सामलाती बोरिंग से करीब 550 फीट कॉपर वायर केबल और स्टार्टर की केबल चोरी कर ले गए। चोरों ने मुख्य प्लास्टिक पाइप लाइन को भी काटकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना से किसानों में रोष है।

भोमिया बाबा के स्थान के समीप श्रीलाल खोड़ा, गोवर्धन खोड़ा और जगदीश खोड़ा की सामलाती बोरिंग लगी है। सुबह खेत पर पहुंचे किसानों को केबल गायब मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज किया।

किसानों ने आसपास तलाश की तो पड़ोसी खेत में केबल के प्लास्टिक कवर की छीलन मिली। आशंका है कि चोरों ने वहीं बैठकर केबल से कॉपर निकाला।

किसानों का कहना है कि थानागाजी क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार नीचे जाने के कारण सिंचाई के लिए 500 से 700 फीट तक बोरिंग करानी पड़ती है। ऐसे में मोटर और केबल चोरी होने से किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ फसलों की सिंचाई भी प्रभावित होती है।

पीड़ित किसानों ने पुलिस प्रशासन से अज्ञात चोरों का पता लगाकर बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत जिले में होंगे विभिन्न कार्यक्रम

भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं आमजन से अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा खैरथल-तिजारा

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली एवं निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार जिले में हर घर तिरंगा अभियान-2026 का आयोजन किया जाएगा। अभियान के तहत जिले के समस्त भूतपूर्व सैनिक, वीर योद्धाओं के परिवारजन अपने-अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अभियान में सहभागिता निभाएंगे तथा तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी [222.द्धड्डह्लद्दद्धड्डह्लह्लद्बह्लड्डठ्ठद्दड्ड.ष्श्वद्व](द्धह्लह्लश्चः//222.द्धड्डह्लद्दद्धड्डह्लह्लद्बह्लड्डठ्ठ-द्दड्ड.ष्श्वद्व) पर अपलोड करेंगे। अभियान के तहत जिले के समस्त गौरव सेनानी, वीरांगनाएं, उनके परिवारजन, सैनिक संगठन एवं आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान को जन-जन तक पहुंचाने एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस से एक दिवस पूर्व स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ शहीद स्मारकों तक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। विद्यालयों में देशभक्ति से ओत-प्रोत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों के साथ संवाद कर स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र सेवा एवं देशभक्ति की भावना से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया जाएगा। जिले के समस्त सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, उनके परिवारजनों, सैनिक संगठनों एवं आमजन से अपील है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान-2026 में उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाएं, अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं तथा तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड कर अभियान को सफल बनाने में योगदान दें।

13 अगस्त को जिले की 6 ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे ग्रामीण सेवा शिविर

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा खैरथल-तिजारा

राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलोअप शिविर 21 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत जिले में 13 अगस्त 2026 को ग्राम पंचायतवार ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 13 अगस्त को उपखंड किशनगढ़बास की ग्राम पंचायत माहोद स्थित अटल सेवा केन्द्र, उपखंड कोटकासिम की ग्राम पंचायत पाटन अहीर स्थित रा.उ.मा.विद्यालय, उपखंड तिजारा की ग्राम पंचायत सरहेटा स्थित अटल सेवा केंद्र, उपखंड टपूकड़ा की ग्राम पंचायत मायापुर स्थित अटल सेवा केंद्र, उपखंड मुंडावर की ग्राम पंचायत पलावा,सिहाली खुर्द स्थित अटल सेवा केन्द्रों पर ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन की विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान, राजस्व प्रकरणों का निस्तारण, पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करना तथा विभिन्न विभागीय सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को शिविरों के सफल संचालन हेतु आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच खेल मैदान में न पानी, न छाया

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा तिजारा

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा के खेल मैदान में परेड और पीटी प्रदर्शन का अभ्यास कर रहे छात्र-छात्राओं को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थी यहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अभ्यास कर रहे हैंभीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बावजूद मैदान में बच्चों के लिए पर्याप्त पेयजल, छाया और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों एवं विद्यालय प्रभारियों में चिंता है। छात्रों ने बताया कि कड़ी धूप में लंबे समय तक अभ्यास करने के दौरान उन्हें पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। विद्यालय प्रभारियों ने मैदान में मौजूद स्टाफ से बच्चों के लिए पानी और छाया की व्यवस्था करने को लेकर बातचीत की। इस दौरान व्यवस्था की जिम्मेदारी को लेकर नगर परिषद की ओर इशारा किया गया। विद्यालय प्रभारियों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी संख्या में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि अभ्यास के दौरान मैदान में तत्काल पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था कराई जाए। गर्मी को देखते हुए मैदान में टेंट लगाने के साथ पानी के टैंकर उपलब्ध कराने और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करने की मांग की गई है। अभिभावकों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान बच्चों से लगातार अभ्यास कराया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि किसी विद्यार्थी की तबीयत खराब होने की स्थिति में तत्काल उपचार मिल सके। विद्यालय प्रबंधन ने भी प्रशासन से समारोह की तैयारियों के साथ बच्चों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने की अपील की है।

स्कूल से लौटने पर मां ने बेटी को गंभीर हालत में पाया, अस्पताल में मृत घोषित

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

अलवर शहर के स्कीम-8 इलाके में बुधवार सुबह एक 16 वर्षीय छात्रा की मौत का मामला सामने आया। छात्रा अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही थी। घटना के समय उसकी मां छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी, जबकि पिता ड्यूटी पर थे। छात्रा को परिजन गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अरावली विहार थाना पुलिस के अनुसार छात्रा 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और नीट की तैयारी के लिए कोचिंग भी कर रही थी। बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे उसकी मां छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकली थी। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो बेटी की हालत देखकर परिजनों को सूचना दी। परिजन तत्काल छात्रा को सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई गीता सैनी ने बताया कि घटना के संबंध में छात्रा के पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि छात्रा पिछले करीब 10-15 दिनों से सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या से परेशान थी। वह दो दिन से स्कूल भी नहीं जा रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्रा अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। उसके दो भाई हैं। पिता स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं और घटना के समय ड्यूटी पर थे। पुलिस घटना से जुड़े परिस्थितियों की जांच कर रही है।

ज्वैलर्स की दुकान में सेंध, चांदी के जेवर और नकदी सहित करीब एक लाख का सामान चोरी

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बर्ड़ोद

बाबा भूतेश्वर महाराज मंदिर के सामने स्थित सांई ज्वैलर्स की दुकान को बुधवार रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर दुकान की साइड की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और चांदी की राखियां, पायल तथा नकदी सहित करीब एक लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। दुकानदार भीम सोनी ने बताया कि वह करीब छह दिन पहले हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए गया था। इसके बाद से दुकान बंद थी। गुरुवार सुबह आसपास के लोगों ने दुकान की दीवार टूटी होने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर वह दुकान पर पहुंचे तो पीछे की दीवार में बड़ा सुराख मिला। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और जांच करने पर चांदी के जेवर तथा नकदी गायब मिली। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया, जिससे घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रभावित होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी हुए सामान की वास्तविक कीमत का आकलन किया जा रहा है।

तिरंगा यात्रा और गृहमंत्री के दौरे को लेकर बनी रणनीति, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा किशनगढ़बास

भाजपा मंडल किशनगढ़बास और मोठूका की संयुक्त बैठक अनाज मंडी स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में आगामी पार्टी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मुख्य रूप से 13 अगस्त को प्रस्तावित मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा और 16 अगस्त को अलवर में होने वाली गृहमंत्री अमित शाह की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा जिला संगठन प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने की। विशिष्ट अतिथियों में जिला संगठन सह प्रभारी गौरव यादव, मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल व राजकुमार राजपूत, चेयरमैन सतीश सिंघल, जिला उपाध्यक्ष राजेश बटवाड़ा, जिला मंत्री सीमा जाटव, पूर्व मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ और छोटेलाल यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक की शुरुआत महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। मुख्य वक्ता रामहेत सिंह यादव ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 13 अगस्त को सुबह 7:30 बजे आयोजित मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया।

बीबीरानी होते हुए कोटकासिम पहुंचेगी यात्रा

रामहेत सिंह यादव ने बताया कि मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा किशनगढ़बास बाईपास स्थित विश्वास यादव डब्बू के कार्यालय से शुरू होगी। इसके बाद यात्रा बीबीरानी होते हुए कोटकासिम पहुंचेगी। बीबीरानी मंदिर से राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य नेता तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

अमित शाह की रैली में अधिक भागीदारी पर जोर

बैठक में 16 अगस्त को अलवर में प्रस्तावित गृहमंत्री अमित शाह की रैली को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी ने कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की ओर से सौंपे जाने वाले प्रत्येक दायित्व को नैतिक जिम्मेदारी मानकर पूरी निष्ठा से पूरा करने का आह्वान किया।

स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों पर शांति-सौहार्द के लिए डीएसपी ने ली सीएलजी बैठक

असामाजिक तत्वों और नशे पर कड़ी नजर रखने के निर्देश

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा तिजारा

तिजारा आगामी त्योहारों और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के उद्देश्य से तिजारा थाना परिसर में डीएसपी शिवराज सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई।बैठक में डीएसपी शिवराज सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय एकता, गौरव और देशभक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश

सीएलजी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से संवाद करें

अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।

नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाए। युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी गई।

त्योहारों के समय नशे में लिप्त होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई* की जाएगी।

स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों के आसपास पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी।

सीएलजी सदस्यों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वे क्षेत्र में शांति समितियों के माध्यम से जागरूकता फैलाएंगे,

बैठक में थाना प्रभारी जयप्रकाश, सुल्तान सिंह, मनोज कुमारी, किशन लाल, बाबूलाल, सुभाष चंद्र, बाबूलाल, जगदीश कुमार, योगेश, समसुद्दीन, नागेंद्र सैनी, विशंभर दयाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

रामस्वरूप दास वाटिका के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइन, हादसे का खतरा

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा माजरीकलां

रैवाणा गांव में बाबा रामस्वरूप दास वाटिका के बीच से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन को लेकर ग्रामीणों ने हादसे की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर बिजली लाइन को वाटिका से बाहर स्थानांतरित कराने की मांग की है।

ग्रामीण बनवारी लाल, राजकुमार डीलर, प्रवीण यादव और ब्रह्मदत्त यादव ने बताया कि बाबा रामस्वरूप तालाब क्षेत्र में पिछले करीब 15 वर्षों से युवाओं की ओर से वाटिका विकसित की जा रही है। यहां बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। आसपास के कायसा, रैवाणा, तलवाना, दोसोद और माजरी खुर्द सहित कई गांवों से लोग रोजाना वाटिका में घूमने और स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि वाटिका के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइन के कारण लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। सिंचाई के दौरान फव्वारे चलने और बारिश के मौसम में बिजली लाइन के आसपास करंट फैलने की आशंका रहती है। ऐसे में वाटिका में आने वाले लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है।

ग्रामीणों के अनुसार बिजली लाइन को करीब 100 मीटर दूर चारागाह भूमि से निकाला जा सकता है। इससे वाटिका में आने वाले लोगों को संभावित खतरे से राहत मिल सकती है और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित नहीं होगी।

ग्रामीणों ने बताया कि लाइन को स्थानांतरित कराने के संबंध में निगम अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने उपखंड अधिकारी से मामले में आवश्यक कार्रवाई कर बिजली लाइन को वाटिका क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कराने की मांग की है।

खटीकन वाली जोहड़ी में बरगद, पीपल, नीम और देशी कीकर के पौधे लगाए

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नीमराना

हरियाली अमावस्या के अवसर पर बुधवार को कस्बे की अरावली पर्वतमाला में स्थित कालिया पहाड़ की ऐतिहासिक खटीकन वाली जोहड़ी की भूमि पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों और युवाओं ने विभिन्न देशी प्रजातियों के पौधे लगाए।

अखिल भारतीय खटीक समाज युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं युवा नेता रिंकू बड़सीवाल ने कहा कि मनुष्य को जीवन में मिलने वाला अधिकांश संसाधन धरती और प्रकृति से ही प्राप्त होता है। औद्योगिक विकास के साथ बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने और क्षेत्र में स्वच्छ हवा एवं ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना जरूरी है।

कार्यक्रम के दौरान पापड़ी, नीम, पीपल, बरगद और देशी कीकर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। आयोजकों ने पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल पर भी जोर दिया, ताकि पौधारोपण का उद्देश्य पूरा हो सके।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ताराचंद बड़सीवाल ने की। उन्होंने गोचर भूमि में पौधारोपण को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण से क्षेत्र में हरियाली बढ़ने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी बेहतर होगा। इस दौरान सज्जन बड़सीवाल, अभय, नैतिक, बेबी देवी, सीमा देवी, रेनू देवी, खुशी, पूजा, रानी, भौरी, ज्योति सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

बीजवाड़ चौहान में जल निकासी के लिए सीवरेज लाइन का काम शुरू

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा शाहजहांपुर

कस्बे के गांव बीजवाड़ चौहान के मुख्य बाजार में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। पंचायत समिति कोटे से इस परियोजना के लिए करीब 6 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। मुंडावर के प्रधान प्रतिनिधि महेश गुप्ता ने बताया कि बारिश के दौरान मुख्य बाजार में पानी भरने से ग्रामीणों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी बाजार में जमा हो जाता था। इसी समस्या को देखते हुए अब सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू कराया गया है। प्रशासन के अनुसार सीवरेज लाइन का काम पूरा होने के बाद बाजार क्षेत्र में पानी की निकासी सुचारु हो सकेगी। इससे बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही दुकानदारों और ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। कार्य शुरू होने के दौरान महेश गुप्ता के साथ बबलू सैनी, संजय सैनी, बलराम चौधरी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए काम शुरू होने पर खुशी जताई और निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा कराने की मांग की।

ई-केवाईसी नहीं कराने पर 48 हजार नाम निलंबित, राशन की दुकान पर करा सकेंगे बहाल

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बहरोड़

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रता और भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण जिले में करीब 1.4 लाख लाभार्थी योजना से बाहर हो गए हैं। इनमें 58,062 लाभार्थी अपात्र पाए गए, जबकि 48,457 लाभार्थियों के ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण उनके नाम निलंबित किए गए हैं। अब इन लाभार्थियों को नाम बहाल कराने का एक और मौका दिया गया है।

ई-केवाईसी के अभाव में निलंबित लाभार्थी अपने ब्लॉक, गांव या वार्ड की किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाना होगा। उचित मूल्य दुकानदार पीओएस मशीन के माध्यम से फिंगरप्रिंट लेकर बायोमैट्रिक सत्यापन करेगा। फिंगरप्रिंट सत्यापित नहीं होने पर आंखों की स्कैनिंग के जरिए भी सत्यापन किया जा सकेगा। ई-केवाईसी पूरी होते ही लाभार्थी का नाम सिस्टम में स्वत: बहाल हो जाएगा।

जिला रसद अधिकारी निकिता राठौड़ ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं होने के कारण निलंबित लाभार्थियों के पास नाम बहाल कराने का अवसर है। लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचकर आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।

वहीं जिले में 44,640 पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। इनमें कोटपूतली में 9,420, पावटा में 7,010, नारायणपुर में 2,970, बहरोड़ में 4,050, बानसूर में 6,270, विराटनगर में 9,640 और नीमराना में 5,280 लाभार्थी शामिल हैं। प्रदेश में 26 जनवरी 2025 से अब तक 89 लाख 14 हजार 235 लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा चुका है।

मानसून सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को तीन महीने का निशुल्क राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा एनएफएसए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के निशुल्क उपचार जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है।

मेन रोड गड्ढों में गुम, तीन साल से मरम्मत का इंतजार

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बहरोड़

कस्बे की मुख्य सड़क पिछले करीब तीन साल से बदहाल स्थिति में है। सड़क की ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है और जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इसके बावजूद अब तक सड़क का पुनर्निर्माण तो दूर, गड्ढों की भी प्रभावी मरम्मत नहीं कराई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।

क्षेत्रवासियों के अनुसार सड़क पर रोजाना आवाजाही के दौरान लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को होती है। सड़क की खराब हालत के कारण वाहन चालकों को कई जगह अचानक गति कम करनी पड़ती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में वाहन चालक अनजाने में गड्ढों में चले जाते हैं और हादसे का खतरा बढ़ जाता है।

यह सड़क स्टेट हाईवे के साथ शहर की विभिन्न कॉलोनियों को जोड़ती है। इसलिए दिनभर यहां बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क की बदहाली के कारण यातायात प्रभावित होने के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब सड़क के कारण वाहनों की रफ्तार कम करनी पड़ती है, जिससे सफर में अधिक समय लगता है। साथ ही वाहनों के टायर, सस्पेंशन और अन्य हिस्सों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जिससे रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है।

क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से सड़क की स्थिति का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सड़क का पुनर्निर्माण कराकर नियमित रखरखाव की व्यवस्था की जाए, ताकि रोजाना होने वाली परेशानी और हादसों पर अंकुश लग सके।

बारिश नहीं हुई तो 18 अगस्त से खुलेगा साबी पुल, आज से बीम की मैस्टिक कोटिंग

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बर्ड़ोद

साबी नदी पर कारोड़ा-सोडावास पुल पिछले 22 दिनों से मरम्मत कार्य के चलते वाहनों के लिए बंद है। बारिश थमने के बाद बुधवार को पुल के सूखने पर मरम्मत कार्य दोबारा शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गईं। बुधवार को मैस्टिक कोटिंग से पहले पुल की सफाई कराई गई और काम में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी मौके पर पहुंचा दी गई।

मरम्मत एजेंसी बालाजी एंटरप्राइजेज, सीकर के सुपरवाइजर प्रकाशचंद जाट के अनुसार पुल की स्पॉट बीम के ज्वाइंटों की मरम्मत पहले ही पूरी की जा चुकी है। अब ज्वाइंटों को मजबूती देने और सड़क की सतह को टिकाऊ बनाने के लिए मैस्टिक कोटिंग की जाएगी। इसके साथ पुल की क्षतिग्रस्त रेलिंग की भी मरम्मत की जाएगी। एजेंसी के अनुसार मौसम साफ रहने पर गुरुवार से मैस्टिक कोटिंग का काम शुरू किया जाएगा। मैस्टिक कोटिंग और रेलिंग की मरम्मत शनिवार तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद पुल की जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

प्रशासन और मरम्मत एजेंसी की योजना है कि यदि बारिश से काम प्रभावित नहीं हुआ तो 18 अगस्त से पुल को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया जाए। पुल बंद होने से कारोड़ा, सोडावास और आसपास के गांवों के वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाहरी वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। पुल के जल्द खुलने की उम्मीद से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की संभावना है। प्रशासन और एजेंसी ने निर्धारित समय में मरम्मत कार्य पूरा करने का दावा किया है।

गांजा बेचने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बहरोड़

कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांजा बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 144 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 10 हजार रुपए है।

थानाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कस्बे के चोबीयन मोहल्ले में एक व्यक्ति गांजा बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

पुलिस ने चोबीयन मोहल्ला निवासी बलवंत उर्फ बबलू (40) पुत्र रोहिताश बाल्मीकि को कथित रूप से गांजा बेचते हुए पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 144 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मादक पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

असामाजिक हो रहे सोशल मीडिया का नियमन जरूरी

उमेश चतुर्वेदी

सोशल मीडिया को लोकतंत्र के बड़े मंच के रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उबाल के बाद देखा जाने लगा। म्यूनिसिपल कर्मचारियों की सख्ती के चलते क्षुब्ध बोआजीजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।

दिल्ली में बीस जुलाई को काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के जेन जी के संबोधन की वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत चर्चा में हैं। चर्चा से ज्यादा उनकी भूमिका कहीं ज्यादा विमर्श के केंद्र में है। इसमें दो राय नहीं कि दुनियाभर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रचलन में हैं, उनमें से ज्यादातर विदेशी हैं। जाहिर है कि वे उन जगहों के कानूनों और सांस्कृतिक परंपराओं से ज्यादा संचालित हैं, जहां उनके मुख्यालय हैं। इसलिए अपने व्यापक हितों के लिए वे अपने प्रचलन वाले देशों की परंपराओं और संस्कृतियों को सवालों के घेरे में लाने, उसका उपहास उड़ाने और उन्हें तार-तार करने वाला अलगोरिदम उन्होंने विकसित कर रखा है। जिसका खामियाजा तीसरी दुनिया के देश और वहां की सांस्कृतिक परंपराएं उठा रही हैं।

सोशल मीडिया को लोकतंत्र के बड़े मंच के रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उबाल के बाद देखा जाने लगा। म्यूनिसिपल कर्मचारियों की सख्ती के चलते क्षुब्ध बोआजीजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। किसी ने इस घटना को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया के तत्कालीन अलगोरिदम ने इस घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया कि समूचे अरब जगत में उबाल आ गया। नागरिक अधिकारों की स्थापना और लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर अरब देशों की जनता सड़कों पर उतर आई। इसका ही नतीजा मिस्त्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर दिखा। जहां महीनों तक लोग जमे रहे और वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। यह आग सीरिया, यमन और लीबिया तक जा पहुंची। वहां के पारंपरिक शासकों के खिलाफ लोगों का दबा हुआ गुस्सा निकला और कई जगह सत्ताएं बदल गईं। भारत में भी इसके ही कुछ महीनों बाद अन्ना हजारे को आगे रखकर एक आंदोलन छेड़ा गया। जिसकी परिणति आम आदमी पार्टी के रूप में हुई और वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। फिर पंजाब में भी उसने पैठ बना ली।

इन घटनाओं को याद करना इसलिए जरूरी है कि इन सबके पीछे सोशल मीडिया के जरिए त्वरित गति से फैलाई गई सूचनाओं का हाथ सबसे ज्यादा रहा। तब सोशल

मीडिया को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया गया। सोशल मीडिया के बारे में कहा गया कि लोकतंत्र में सबकी आवाज पहुंचाने और उन्हें मौका देने का यह बड़ा माध्यम है। इसे लोकतंत्र के वाजिब और जरूरी औजार के रूप में भी मान्यता मिली। लेकिन बीतते वक्त के साथ पता चल रहा है कि जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, वह लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अनसोशल यानी असामाजिक भी है। यह ठीक है कि सोशल मीडिया के जरिए व्यवस्था की अंधी सुरंग में खो रही आवाजों को मौका मिलता है। लेकिन यह उतना ही सच है कि इस माध्यम ने लोगों की नजर का पानी उतार दिया है। लोग अब लिहाज करना भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर अगर किसी की बात पसंद नहीं आती तो उसे खुलेआम गालियां दी जा सकती हैं। उसके चरित्र पर आक्षेप लगाया जा सकता है। उसका चरित्र हनन किया जा सकता है। चाहे वह व्यक्ति सामाजिक जीवन में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो, उसकी उम्र चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो।

सोशल मीडिया मंचों ने अपना अलगोरिदम भी ऐसा विकसित किया है, जो अच्छी बातों, सामाजिक चिंतन और बेहतर कल की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देखा। एक तरह से कहें तो वह इसकी अनदेखी ही करता है। लेकिन जैसे ही किसी को कोई गाली देता है, किसी के चरित्र का बेवजह ही हनन करता है, किसी का घटिया कार्टून बनाता है, सोशल मीडिया का अलगोरिदम उसे फैलाने में द्रुत गति से जुट जाता है। सोशल मीडिया ने अब तक पर्दे के पीछे रही नंगई को भी उजागर कर दिया है। आज रील्स के चक्कर में अधनंगे और कई बार करीब-करीब नग्न फोटोग्राफ और वीडियो तक जारी किए जा रहे हैं। भले ही अपने परिवारों में महिलाएँ और युवतियां सलीके से रहती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने और उसके जरिए कुछ कमाने के चक्कर में अपने शील और अपनी लज्जा को भी बेपर्दा कर रही हैं। सोशल मीडिया कितना असमाजिक हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका अलगोरिदम अश्लीलता को बढ़ावा देता है, लेकिन शील और लज्जा की बात को अपने मंच के किसी कोने में डाल देता है। कह सकते हैं कि वर्चुअल स्पेस के किसी अंधेरे कोने में उसे गुम कर देता है।

तीन साल पहले प्यू रिसर्च सेंटर ने 19 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में सोशल मीडिया को लेकर एक शोध किया था। उसके मुताबिक, आम नागरिकों की नजर में सोशल मीडिया राजनीतिक जीवन के लिए रचनात्मक और विनाशकारी दोनों है। इस अध्ययन में शामिल देशों में, औसतन 57 प्रतिशत लोगों ने माना कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन इसे बिनाशकारी मानने वालों की संख्या भी कम नहीं रही। करीब 35 प्रतिशत से ज्यादा लोगों का का कहना था कि सोशल मीडिया विनाशकारी साबित हो रहा है। सिर्फ 34 प्रतिशत अमेरिकियों ने ही सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए लाभकारी माना, जबकि 64 फीसद का कहना था कि इसने नकारात्मक प्रभाव ज्यादा डाला है। हाल ही में जेन जी से चर्चा के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी सोशल मीडिया को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि सोशल मीडिया पर उनके कारण दस लाख लोग कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक, उपयोगी और समाजहित की सामग्री साझा करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर केवल प्रामाणिक स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। जेन-जी में भी यह विवेक विकसित होना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। वरिष्ठ पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वह नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करे तथा उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझाए।

सोशल मीडिया का अनसोशल चेहरा और मंच आर्थिक कमाई का जरिया भी है। नंगई, हिंसा और व्यभिचार-अतिचार की कहानियां, दृश्य, वीडियो और फोटो को वायरल करने में उसका कोई सानी नहीं है। इस बहाने इसे प्रसारित करने वाले को सोशल मीडिया मंच आर्थिक कमाई भी कराते हैं। और तो और, वे खुद भी ऐसी घटनाओं, दृश्यों को प्रसारित-प्रचारित और वायरल करने के लिए बड़ी रकम लेते हैं। संसदीय समिति के सामने फेसबुक और इंस्टाग्राम की संचालक कंपनी मेटा के अधिकारियों ने माना है कि काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान गाली, हिंसा आदि को बढ़ावा देने के लिए पैसे भी लिए थे। इन कोशिशों का मकसद भारत में व्यापक पैमाने पर लोगों को उत्तेजित करके अराजकता फैलाना था। इस लिहाज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में लोकतंत्र की रक्षा के मुखौटे के पीछे से दखल भी दे रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती भी दे रहे हैं। वक्त आ गया है कि इनके नियमन के लिए कठोर कानून बनाए जाएं। जिसके तहत उन्हें अभिव्यक्ति के अधिकार को बढ़ावा देने की व्यवस्था तो हो, लेकिन इसकी आड़ में अराजकता फैलाने की छूट नहीं।

संपादकीय

पैलेट के जख्म

इसमें दो राय नहीं कि किसी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के किन्हीं परिस्थितियों में उग्र होने और जन-धन की हानि रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई करनी होती है। इसमें भी दो राय नहीं है कि राज्य के पास हिंसा को रोकने और कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे विरोध को रोकने के लिए प्रयोग की गई ताकत का स्तर क्या रहा। जाहिर है राष्ट्रविरोधी ताकतों, हिंसक भीड़ तथा छात्रों के आंदोलन को एक ही तौर-तरीके से नहीं निपटा जा सकता है। इसी आलोक में सवाल पैदा होता है कि जंतर-मंतर से शुरू हुए संसद चलो मार्च को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई ताकत क्या जरूरी थी? क्या उचित तरीके से अधिकृत थी? ऐसा ही विवाद इस आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर खड़ा हुआ है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शुरूआत से ही पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया। जबकि बाद में जनरल डायरी में यह दर्ज किया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने एंटी-रायट गन से दो राउंड फायरिंग की थी। वहीं दूसरी ओर छात्र प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। खासकर, कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने गृह मंत्री पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तीखे प्रहार किए हैं। वे बाकायदा गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे हैं। इसी बीच सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली के दो अस्पतालों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार बीस जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम दस लोगों को पैलेट गन से चोट लगी थी। इन अस्पतालों में पैलेट गन से आहत छात्रों ने उपचार कराया था। निस्संदेह, पैलेट गन से घायल होने वालों का यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है, न कि किसी बिना पुष्टि वाले दावों पर आधारित है। दरअसल, पैलेट गन की जद में आये छात्रों के अनुभव परेशान करने वाले रहे हैं। खबरों के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों के चेहरों, छाती और आंखों पर चोट आई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि एक छात्र की आंख की रोशनी भी जा सकती है। सार्वजनिक विमर्श में सवाल उठाये जाते रहे हैं कि छात्र आंदोलनकारियों के विरुद्ध पैलेट गन का इस्तेमाल करने का तार्किक आधार क्या है। वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के दौरान मेटल पैलेट गन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

चिंतन-मनन

जो नहीं है उसे पाना हो ध्येय

असंतुष्ट होने का अर्थ दुखी होना नहीं है। असल में कोई आदमी पूरी तरह सुखी होकर भी असंतुष्ट हो सकता है। सुखी होने का मतलब है, जो है, उसे आनंद से भोगना। और असंतुष्ट होने का अर्थ हैः जो नहीं है उसे आनंद से पैदा करने का श्रम करना। जब अधिकतम लोग समाज में इस भांति श्रम करते हैं तो समाज संपन्न और समृद्ध होता है। और जब अधिक लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है बस ठीक है, वही रुक जाना है, तो फिर पूरा समाज धीरे-धीरे दरिद्र हो जाता है। जिंदगी का सारा विकास, जो नहीं है, उसे पाने से ही होता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि ऐसा किसी जगह मानने की जरूरत नहीं है कि अब सब पूरा हो गया, अब भला मुझे क्या करना है! यह मरने के ढंग हैं। यह अपने भीतर जिंदा रहते हुए मर जाना है। जब तक श्वास है, तब तक एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मेरी तो सच में ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो गईं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को दूसरों की आवश्यकताएं पूरा करने में लग जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पक्का ऐसा लगता है कि मेरी तो सभी आवश्यकताएं पूरी हो गईं, मैं क्यों श्रम करूं? तो उसे चारों तरफ देखना चाहिए कि अब मेरा काम तो जमीन पर खत्म हो गया, लेकिन दूसरों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, उनके लिए मैं श्रम करने में लग जाऊं। लेकिन श्रम से नहीं बचा जा सकता। आपकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, तो अपने चारों तरफ देखिए। बहुत लोगों की पूरी नहीं हुई हैं, अतः उनके लिए श्रम करने में लग जाइए। लेकिन खाली बैठने का हक किसी को नहीं है। संन्यासी को भी खाली बैठने का हक नहीं है। देश को संपन्न करना है तो सभी को श्रम में लगना ही चाहिए। और श्रम में हम तभी लगेंगे जब कोई आवश्यकता पूरी करनी हो। चाहे अपनी, चाहे किसी दूसरे की, लेकिन आवश्यकता पूरी करने की दौड़ जारी रहनी चाहिए। यह दौड़ शांत हो, यह दौड़ आनंदपूर्ण हो, इतना मैं कहूंगा। यह दौड़ पागल की नहीं होनी चाहिए, विक्षिप्त की नहीं होनी चाहिए। यह दौड़ नींद को हराम कर देने वाली नहीं होनी चाहिए। यह दौड़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आदमी बिल्कुल होश खो दे और दौड़ता रहे, और उसे पता भी न हो कि कहां दौड़ रहा है। यह दौड़ बहुत आनंदपूर्ण होनी चाहिए, यह दौड़ बहुत शांत होनी चाहिए, यह दौड़ बहुत स्वस्थ होनी चाहिए। यह हो सकती है। लेकिन हमने इस तरफ सोचा नहीं

अंगदान की संस्कृति ही मानवता को नई दिशा दे सकती है

ललित गर्ग

मनुष्य जीवनभर अपने लिए बहुत कुछ अर्जित करता है-धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, संबंध और सुविधाएँ। लेकिन जीवन की अंतिम घड़ी में इन सबका महत्व समाप्त हो जाता है। तब यदि हमारे शरीर का कोई अंग किसी दूसरे मनुष्य की धड़कन बन जाए, हमारी आँखें किसी अंधेरे जीवन में रोशनी भर दें, हमारा यकृत या गुर्दा किसी परिवार के बुझते चिराग को फिर से जला दे, तो इससे बड़ी जीवन-सार्थकता और क्या हो सकती है? अंगदान मृत्यु के बाद भी जीवन को जारी रखने की वह मानवीय संभावना है, जो मनुष्य को केवल अपने लिए जीने वाले प्राणी से उठाकर मानवता के लिए जीने वाला बना देती है। विश्व अंगदान दिवस हमें इसी महान विचार से जोड़ता है। आज आवश्यकता केवल अंगदान के बारे में जानकारी देने की नहीं, बल्कि हमारी सोच बदलने की है। हमें यह प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि जिस शरीर को मृत्यु के बाद पंचतत्व में विलीन होना है, उसके उपयोगी अंग यदि किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं तो उन्हें अपने साथ मि ी में मिला देना अधिक सार्थक है या किसी की सांसों का हिस्सा बना देना? मृत्यु नि ित है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन का कारण बनना हमारे हाथ में है।

भारत की सांस्कृतिक स्मृति में शरीर और जीवन के महान त्याग की परंपरा बहुत पुरानी है। महर्षि दधीचि की कथा इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। पौराणिक परंपरा के अनुसार जब देवताओं को असुरों से संघर्ष के लिए ऐसे अस्त्र की आवश्यकता हुई जिसे दधीचि की अस्थियों से बनाया जा सके, तब महर्षि दधीचि ने लोककल्याण के लिए अपना शरीर ही त्याग दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और उससे जनकल्याण की रक्षा हुई। यह कथा आधुनिक अर्थों में अंगदान की चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अपने शरीर को भी समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर देने की भारतीय त्याग-चेतना का अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक अवश्य है। भारत के राष्ट्रपति सचिवालय ने भी अंग एवं देहदान की भारतीय परंपरा को समझाते हुए महर्षि दधीचि के इस प्रसंग का उल्लेख किया है। हमारी परंपरा में राजा शिवि की कथा भी त्याग और जीव-दया की अद्भुत मिसाल है। एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस तक देने की तत्परता दिखाई। चाहे ये प्रसंग धार्मिक आख्यान हों, लेकिन इनके भीतर छिपा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है-अपने जीवन और शरीर को केवल अपनी निजी संपत्ति न समझना, बल्कि उसे व्यापक जीवन के कल्याण से जोड़ना। जैन दर्शन का सूत्र परस्परोपग्रहो जीवानाम् भी यही बताता है कि जीव एक-दूसरे के उपकार के लिए हैं। अंगदान इस विचार का आधुनिक वैज्ञानिक रूप कहा जा सकता है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इस मानवीय भावना को वास्तविक जीवन बचाने की शक्ति प्रदान कर दी है। वर्ष 1954 में दुनिया का पहला सफल मानव किडनी प्रत्यारोपण हुआ। रोनाल्ड ली हेरिक ने अपनी एक किडनी अपने जुड़वां भाई रिचर्ड को दान की थी। यह घटना चिकित्सा इतिहास में एक ऐसी क्रांति की शुरूआत बनी, जिसने आगे चलकर अंग प्रत्यारोपण को लाखों लोगों के लिए जीवन की आशा बना दिया। इसके बाद 1967 में मानव हृदय प्रत्यारोपण की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि चिकित्सा विज्ञान मनुष्य की मृत्यु और जीवन के बीच खड़ी कई दीवारों को तोड़ सकता है। भारत ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय यात्रा की है। देश में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण 1 दिसंबर 1971 को चेन्नई के क्रि यन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर में हुआ था। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन भारत में हजारों लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण जीवन का नया द्वार बनेगा। आज चिकित्सा तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किडनी, लिवर, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय और आंत जैसे अंगों के साथ कॉर्निया, त्वचा, हड्डी और हृदय वाल्व जैसे ऊतकों का भी प्रत्यारोपण संभव है।

लेकिन विज्ञान की क्षमता जितनी बढ़ी है, हमारी सामाजिक चेतना उस गति से नहीं बढ़ पाई। यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में आज भी प्रत्यारोपण की आवश्यकता और उपलब्ध अंगों के बीच बड़ा अंतर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024 में देश में अंग प्रत्यारोपण की गतिविधि व्यापक रही, लेकिन मृतक दाताओं की संख्या अभी भी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ साफ है-हमारे अस्पतालों में तकनीक है, डॉक्टर हैं, सर्जरी की क्षमता है, लेकिन जीवन बचाने के लिए पर्याप्त अंग नहीं हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें अंगदान को मृत्यु की चर्चा नहीं, जीवन की चर्चा बनाना होगा। परिवारों में इस विषय पर समय रहते बातचीत होनी चाहिए। स्कूलों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया को मिलकर ऐसी वातावरण-निर्मिति करनी होगी जिसमें अंगदान सुनते ही भय नहीं, बल्कि करुणा और जीवन बचाने का भाव पैदा हो। आज भी अनेक लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर को क्षति पहुँचाना धर्म के विरुद्ध है। कुछ लोगों को अगले जन्म की चिंता होती है, कुछ को शरीर के साथ होने वाली चिकित्सा प्रक्रिया का भय होता है और कुछ परिवार अंतिम समय में मानसिक रूप से इतने टूट जाते हैं कि अंगदान का निर्णय नहीं ले पाते। इन भ्रमों का समाधान टकराव से नहीं, संवाद, संवेदना और वैज्ञानिक जानकारी से होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी होगी कि अंगदान किसी पर थोपा जाने वाला धार्मिक या सामाजिक कर्तव्य नहीं है। यह एक स्वैच्छिक, नैतिक और मानवीय निर्णय है, जिसे व्यक्ति को विश्वसनीय चिकित्सा एवं कानूनी जानकारी के आधार पर लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यह संकल्प करता है कि मृत्यु के बाद उसके उपयोगी अंग किसी जरूरतमंद को मिलें, तो वह अपने जीवन की अंतिम घड़ी को भी मानवता के उत्सव में बदल सकता है। भारत में अंगदान की प्रेरक घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में नागपुर में 52 वर्षीय शिक्षक कोंडबा दत्तात्रेय मडावी मृतक अंगदान करने वाले 200वें दाता बने, उनके अंगों से तीन लोगों को नया जीवन मिला। ऐसी घटनाएँ हमें बताती हैं कि अंगदान कोई दूर की आदर्शवादी कल्पना नहीं, बल्कि हमारे आसपास घटने वाली वास्तविक जीवन-बचाने वाली प्रक्रिया है। दिल्ली में 70 वर्षीय मृत महिला के गुर्दों का सफल उपयोग कर एक 56 वर्षीय महिला को जीवन की नई उम्मीद मिली-यह घटना यह भी बताती है कि केवल उम्र के आधार पर किसी संभावित दाता के अंगों को अनुपयोगी मान लेना उचित नहीं है, अंतिम निर्णय चिकित्सा स्थिति पर निर्भर करता है। भारत के कुछ राज्यों ने इस दिशा में उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में 2024 में मृतक अंगदान की दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रही और उसके जीवदान कार्यक्रम के माध्यम से हजारों प्रत्यारोपण संभव हुए। तमिलनाडु में भी मृतक अंगदान की व्यवस्था ने अनेक परिवारों को प्रेरित किया हैय 2026 में एक परिवार ने भाषा की बाधा के बावजूद डिजिटल अनुवाद की मदद से अपने प्रियजन के अंगदान का निर्णय लिया और अनेक मरीजों को जीवन मिला।

जंतर मंतर-रांचीः छात्र आंदोलन एक रूप अनेक

निर्मल रानी

देश इन दिनों लगभग राष्ट्रव्यापी छात्र आक्रोश व आंदोलन से रूबरू है। अभी कुछ दिन पहले ही नीट पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ 6 जून से शुरू होकर 25 जुलाई 2026 तक चला आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ था। इसके बाद ही झारखंड में भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरुद्ध 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन की शुरूआत हुई। यहाँ भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, धांधली और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच आदि मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। परन्तु कुछ दिनों पूर्व हुये दिल्ली के जंतर-मंतर व वर्तमान समय रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में जहां कुछ बातें समान हैं वहीं कई बातें विरोधाभासी भी हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों ही आंदोलन पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई धांधली व अनियमितताओं के खिलाफ किये गए हैं। जंतर मंतर की ही तरह रांची में भी जहाँ आंदोलनस्थल पर अनेक स्वयंसेवी लंगर चला रहे हैं व आंदोलनकारी छात्रों के दूर दराज बैठे समर्थक फूड ऐप्स के जरिए सीधे आंदोलन स्थल पर भोजन ऑर्डर कर रहे हैं व छात्रों को मेडिकल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ भी भोजन इतनी अधिक मात्रा में आ रहा है कि आंदोलनकारी छात्रों ने वीडियो जारी कर लोगों से कुछ दिन ऑर्डर रोकने की अपील की ताकि खाना बर्बाद न हो और बचे हुए भोजन को जरूरतमंदों में बांटा जा सके। इसके अलावा रांची के स्थानीय दुकानदारों और आम नागरिकों द्वारा आंदोलन स्थल पर भोजन,समोसे, बिरयानी,नाश्ता और पानी आदि पहुंचाया जा रहा है। अनशन पर बैठे छात्र नेताओं की सेहत की देखभाल के लिए रांची के सदर अस्पताल में मेडिकल टीम नियमित रूप से आंदोलन स्थल पर पहुंचकर स्वास्थ्य जांच (ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल) कर रही है। इसके अतिरिक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने निर्देश जारी किया है कि आंदोलन के दौरान बीमार या चोटिल होने वाले छात्रों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, चाहे वे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं या निजी अस्पताल में।

परन्तु इन दोनों अर्थात दिल्ली व रांची के आंदोलन में जो सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है वह है जंतर मंतर के छात्र आंदोलन का विरोध करने वालों का रांची के आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लेना। बड़ी हैरत की बात है कि जो वर्ग,जो संगठन और जिस विचारधारा से जुड़े लोग जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को देशद्रोही, बदतमीज, गटर जनरेशन,गलियां बोलने व अपशब्द इस्तेमाल करने वालों का झुण्ड,विदेशी फंडिंग से चलने वाला आंदोलन बता रहे थे, दिल्ली के आंदोलन में जो लोग हिन्दू-मुस्लिम का दृष्टिकोण ढूंढ रहे थे,जिन्हें दिल्ली के आंदोलन कारी आवारा व चरित्रहीन नजर आ रहे थे वही लोग वही वर्ग और वही विचारधारा रांची के छात्र आंदोलन में कुछ इसतरह बढ़चढ़कर हिस्सा लेने को उतावली है गोया रांची का आंदोलन छात्र आंदोलन के बजाये देश का दूसरा स्वाधीनता संग्राम हो? याद कीजिये कि जंतर मंतर आंदोलन के संदर्भ में ही एक हिंदुत्व विचारक और केरल भाजपा के बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास ने कहा था कि अगर स्थिति उनके नियंत्रण में होती, तो वे नई दिल्ली के आंदोलन स्थल के आसपास कर्फ़्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा देते। इस व्यक्ति ने प्रदर्शन में शामिल धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी विचारधारा वाली छात्राओं व महिलाओं के साथ रेप करवाने जैसी बेहद अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थीं। साथ ही गोदी मीडिया के नाम से बदनाम सत्ता का पिछलग्गू मीडिया भी जो जंतर मंतर आंदोलन से या तो मुंह मोड़े हुआ था या इसी आंदोलन विरोधी वर्ग की तरह आंदोलन में केवल नकारात्मकता तलाश रहा था,जिसे संसद भवन के पास चल रहा इतना बड़ा छात्र आंदोलन नजर नहीं आ रहा था वही मीडिया रांची में डेरा जमाये हुये है और अपने तरीके से छात्र आंदोलन का नरेटिव सेट करने में लगा है। इस दोहरेपन का केवल एक ही कारण है कि दिल्ली में केंद्र व दिल्ली राज्य, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जबकि झारखण्ड में झारखंड मुक्ति मोर्चा , कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, के गठबंधन यानी इण्डिया गठबंधन की सरकार है और झामुमो के हेमंत सोरेन इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। इसलिये इनका समर्थन छात्र आंदोलन को नहीं बल्कि यह झारखण्ड में इण्डिया गठबंधन की सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस अवसरवादी विचारधारा का विरोध करने वालों का चेहरा रांची में उस समय भी बेनकाब हुआ जबकि जंतर मंतर के आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और वहां अनशन पर बैठने वाली अखिल भारतीय छात्र संगठन AISA की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जब हजारों छात्रों के साथ विधानसभा के लिये मार्च निकाल रही थीं उस समय एक युवक ने नेहा पर स्याही फेंक कर छात्र आंदोलन को समर्थन देने की अपनी हकीकत को उजागर कर दिया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। नेहा बोरा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिनके पास तर्क या बहस की क्षमता नहीं होती, वे ऐसी हरकतों पर उतर आते हैं। उन्होंने इस हमले के पीछे भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि नेहा बोरा व उनका संगठन अखिल भारतीय छात्र संगठन AISA जंतर मंतर के आंदोलन में भी शामिल था और उसी उत्साह के साथ रांची में भी सक्रिय है। जबकि रांची में छात्र आंदोलन का मुख्य चेहरा बनने की इच्छा पालने वाले लोग जंतर मंतर में न केवल लापता थे बल्कि उसके विरोध में भी खड़े थे। कहा जा सकता है कि जंतर मंतर व रांची दोनों जगह छात्र आंदोलन व उनकी मांगें व समस्याएँ तो लगभग एक हैं परन्तु उनके अनेक रूप देखे जा रहे हैं।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि 15 अगस्त

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटपूतली

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा संख्या 32 के तहत संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। योजना का संचालन निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर के माध्यम से किया जा रहा है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी विपिन ने बताया कि योजना के तहत प्राप्त आपत्तियों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाएगा। संबंधित आवेदकों को 15 अगस्त तक अपनी आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी करवाना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे शिक्षा, रोजगार और अन्य आवश्यक गतिविधियों से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। योजना के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को आवागमन में सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग ने योजना के पात्र आवेदकों से अपील की है कि वे आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। विभाग के अनुसार 15 अगस्त के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

श्यामेश्वर धाम मार्ग पर 80 लाख से बनेगा भव्य श्याम द्वार

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा रामगढ़

श्यामेश्वर धाम मंदिर मार्ग पर अब श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य श्याम द्वार का निर्माण होगा। तोरणद्वार के निर्माण को डीएलबी से मंजूरी मिलने के बाद नगरपालिका रामगढ़ ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना पर करीब 80 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव और स्थानीय विधायक सुखवंत सिंह की घोषणा के बाद नगरपालिका की ओर से परियोजना की तकनीकी रिपोर्ट और लागत अनुमान तैयार किया गया था। इसके आधार पर डीएलबी से निर्माण की स्वीकृति मिली है। अधिशाषी अधिकारी जगदीश खीचड़ ने बताया कि स्वीकृति मिलते ही निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। विधायक सुखवंत सिंह के अनुसार श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुरोध पर मंदिर मार्ग पर भव्य तोरणद्वार बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नगरपालिका अधिकारियों को लागत अनुमान और आवश्यक तकनीकी दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल ने बताया कि प्रस्तावित श्याम द्वार का निर्माण महात्मा गांधी बालिका स्कूल के पास किया जाएगा। इसकी आंतरिक चौड़ाई 40 फीट, बाहरी चौड़ाई 50 फीट और ऊंचाई 48 फीट रखी गई है। डिजाइन में 40 फीट के बाद 8 फीट की छतरियां भी शामिल होंगी। विधायक ने बताया कि तोरणद्वार के निर्माण के बाद श्यामेश्वर धाम मंदिर मार्ग को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर धार्मिक और पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा।

रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आई महिला, दोनों पैर कटे

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम रेलवे ट्रैक पार करते समय 32 वर्षीय महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में महिला के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार घटना अलवर-जयपुर रेलवे ट्रैक पर बंदीपुरा गांव के पास हुई। कलसाड़ा निवासी रुकसार खान खेत से काम कर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान वह रेलवे ट्रैक पार करने लगी। ट्रैक पार करते समय अचानक रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। महिला फिसलकर ट्रैक पर गिर गई और ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे के बाद ट्रेन को मौके पर रोक दिया गया। लोको पायलट ने घटना की सूचना स्टेशन मास्टर को दी। सूचना मिलने पर मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल अलवर भिजवाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अलवर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अलवर का नाम अब भारतरत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। अब कॉलेज का नाम भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर होगा। राजमेस के माध्यम से संचालित इस मेडिकल कॉलेज का पहला सत्र वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। इस वर्ष कॉलेज में चौथा बैच प्रवेश लेगा। वर्तमान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 100 सीटें निर्धारित हैं। आगामी सत्र में यहां पीजी पाठ्यक्रम शुरू होने की भी संभावना जताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का लोकार्पण 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से नामकरण का आदेश जारी होने के बाद कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया है। करीब 127 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का निर्माण पूरा हुआ है। इसके लोकार्पण की तैयारियां चल रही हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों प्रथम चरण का लोकार्पण कराने की तैयारी की जा रही है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होने के साथ ही 16 अगस्त को प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भी प्रशासन और चिकित्सा विभाग की तैयारियां तेज हो गई हैं। आने वाले समय में पीजी पाठ्यक्रम शुरू होने से मेडिकल शिक्षा के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की उम्मीद भी है।

बूढ़वाल-भूपखेड़ा में 16 लाख से अधिक की सीसी सड़कों का उद्घाटन

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बहरोड़

क्षेत्र के बूढ़वाल और भूपखेड़ा गांव में बुधवार को पंचायत समिति प्रधान कोटे से 16 लाख रुपए से अधिक की लागत से तैयार सीसी सड़कों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने सड़कों का उद्घाटन किया। इस दौरान गांव के भामाशाह खुशीराम मास्टर ने गांव में स्वागत द्वार बनवाने की घोषणा की। ग्रामीणों ने घोषणा का स्वागत किया और गांव के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान बस्तीराम यादव ने 16 अगस्त को प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अलवर रैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने ग्रामीणों से गांव से एक बस में करीब 50 लोगों के अलवर पहुंचने का आह्वान किया। अपील के बाद ग्रामीणों ने बस भरकर रैली में जाने पर सहमति जताई। कार्यक्रम में सरपंच कपिल यादव, पंचायत समिति सदस्य सुनील यादव सहित ग्रामीण और अन्य लोग मौजूद रहे।

नियमों को ताक पर रख फोरलेन निर्माण, जलभराव के खतरे से ग्रामीणों में आक्रोश

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटपूतली

स्टेट हाईवे-37 बी के फोरलेन चौड़ीकरण कार्य में ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नारेहड़ा और सरूंड क्षेत्र में निर्माण एजेंसियों, RSRDC, PWD और ठेकेदार पर तकनीकी मापदंडों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर अर्पणा गुप्ता को लिखित शिकायत सौंपी। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के दूसरी तरफ और नारेहड़ा गांव की ओर से आने वाले पानी को ह्यूम पाइप के जरिए जबरन एक तरफ की सिंगल नाली में डाला जा रहा है। उनका कहना है कि दो दिशाओं से आने वाले पानी को एक तरफ मोड़ने पर नाली और पाइप की क्षमता बढ़ाना जरूरी है, लेकिन निर्माण में पर्याप्त क्षमता का प्रावधान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने इसे भारतीय सड़क कांग्रेस के ड्रेनेज कोड IRC:SP:42-2014 के प्रावधानों के विपरीत बताया है। ग्रामीणों के अनुसार मौके पर आपत्ति जताने पर अधिकारियों की ओर से बजट की कमी और आगे बसावट नहीं होने जैसे तर्क दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रभावित स्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नदी मौजूद है। यदि नाली को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाकर नदी से जोड़ा जाए तो जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।

ग्रामीणों ने चेताया कि मानसून के दौरान ड्रेनेज क्षमता कम होने से पानी बैक मार सकता है। इससे पावरहाउस के पास स्थित ऐतिहासिक श्री हनुमान वेद निकेतन मंदिर, दुकानों, मकानों और कृषि भूमि में जलभराव की स्थिति बन सकती है। लंबे समय तक गंदा पानी जमा रहने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई गई है।

ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवाद संख्या 072607128026622 के तहत शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनका आरोप है कि अब तक संतोषजनक समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मांग की कि नाली का निर्माण तकनीकी मानकों के अनुसार कर उसे प्राकृतिक नदी तक जोड़ा जाए। शिकायत के दौरान सरपंच प्रतिनिधि अशोक सिंह सहित प्रशांत भारद्वाज, नरेश यादव, महेंद्र यादव, वीरेंद्र सिंह, सुरेश शर्मा, संजय जोशी, सुरजन मीणा, विजय यादव, पवन सिंह, मोहित यादव, सौभाग्य यादव, रामपाल कुमावत, कैलाश, सुनील सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने लिया जायजा

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटपूतली

आगामी 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने बुधवार को एलबीएस महाविद्यालय मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने समारोह स्थल पर चल रही तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर ने मंच, अतिथियों एवं आमजन की बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि समारोह के दौरान आमजन और आमंत्रित अतिथियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह में होने वाली परेड की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। परेड में शामिल होने वाले विभिन्न दलों की तैयारियों की जानकारी लेते हुए उन्होंने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए समारोह का आयोजन पूरी गरिमा और सुव्यवस्था के साथ किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए उन्हें सौंपे गए दायित्वों का समय पर निर्वहन करें। उन्होंने समारोह स्थल पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के साथ स्वच्छता, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एएसपी नाजिम अली, नगर परिषद आयुक्त अरुण शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे।

समझाइश के बाद ठाकुरजी मंदिर के पास से हटाया अतिक्रमण

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नारायणपुर

ग्राम पंचायत चांदपुरी के गांव राजपुरा सिक्ख में ठाकुरजी मंदिर के पास किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने बुधवार को समझाइश के बाद हटवा दिया। मंदिर के आसपास कच्चे-पक्के निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और संबंधित लोगों से बातचीत की।

प्रशासन ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को समझाइश दी। इसके बाद आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। जेसीबी की सहायता से मौके पर कच्चे-पक्के निर्माण हटाए गए और मंदिर के आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार कैलाश चंद मेहरा, ग्राम विकास अधिकारी रीना यादव और प्रशासक मंजू देवी मौजूद रहे। प्रशासन की कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे।

अधिकारियों ने बताया कि समझाइश के बाद शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की गई। प्रशासन ने क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद मौके की स्थिति का जायजा भी लिया।

अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, रास्तों पर खोदी गहरी खाई

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा शाहजहांपुर

थाना क्षेत्र के घीलोठ इलाके की पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने अवैध खनन और खनन सामग्री के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रास्तों पर गहरी खाई खोदकर उन्हें बंद कर दिया, ताकि वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार नीमराना डॉ. विक्रम सिंह, शाहजहांपुर थाना प्रभारी प्रकिता सिंह और खनिज विभाग के शिवांग पारीक सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। संयुक्त टीम ने घीलोठ क्षेत्र की पहाड़ियों का निरीक्षण किया और अवैध खनन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रास्तों को चिह्नित कर उन्हें बंद करने की कार्रवाई की।

अधिकारियों के अनुसार खनन सामग्री के परिवहन के लिए इन रास्तों से वाहनों की आवाजाही होती थी। रास्तों पर गहरी खाई खोदने से खनन माफिया के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने की उम्मीद है।

तहसीलदार डॉ. विक्रम सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की बात भी कही है।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत एलबीएस कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटपूतली

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। देशभक्ति से ओतप्रोत इस प्रतियोगिता में स्वयंसेविकाओं और अन्य छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया।

प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रंगोली के माध्यम से तिरंगे और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को आकर्षक रूप में उकेरा। विभिन्न रंगों और डिजाइनों से तैयार रंगोलियों ने कार्यक्रम स्थल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।

प्रतियोगिता के परिणाम में विनीता शर्मा ने उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। पलक मीणा द्वितीय स्थान पर रहीं, जबकि काजल और कोमल शर्मा ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान हासिल किया।

निर्णायक मंडल में वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रो. सुमन पूनियां, कार्यक्रम अधिकारी प्रो. शुभलता यादव और कार्यक्रम अधिकारी प्रो. संदीप कुमार आर्य शामिल रहे। प्रतियोगिता के समापन पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. राजेंद्र कुमार सिंह ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया।

राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक प्रो. अशोक सिंह ने एनएसएस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को देशहित और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रो. चंदन सिंघल ने सभी का आभार व्यक्त किया।

कोटपूतली में गूंजेगा नवाचार का डंका, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटपूतली

राजस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता की विषयवस्तु 'सतत विकास के लिए विज्ञान और नवाचार' रखी गई है। इसका उद्देश्य 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, शोध क्षमता और स्थानीय समस्याओं के समाधान की समझ विकसित करना है।

कोटपूतली जिला समन्वयक मुकेश वर्मा और सुशील मुलोदिया ने बताया कि प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर दो वर्गों में होगी। जूनियर वर्ग में 10 से 14 वर्ष तथा सीनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रत्येक टीम में दो विद्यार्थी और एक मार्गदर्शक शिक्षक शामिल होंगे। विद्यार्थियों को अपने आसपास की किसी स्थानीय समस्या का चयन कर उसका सर्वेक्षण, आंकड़ा संग्रह और वैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा। इसके आधार पर मॉडल, प्रोटोटाइप, पीपीटी या पोस्टर के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रतियोगिता में पांच प्रमुख उप-विषयों को शामिल किया गया है। इनमें कचरा प्रबंधन एवं रिड्यूस-रीसायकल, ऊर्जा के नए विकल्प एवं प्रयोग, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, भोजन-कृषि-स्वास्थ्य तथा सतत विकास में भारतीय ज्ञान प्रणाली की उपयोगिता शामिल हैं। विद्यार्थियों को इन विषयों में से किसी एक का चयन कर अपनी परियोजना तैयार करनी होगी। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा। जिला स्तरीय चरण अक्टूबर 2026, राज्य स्तरीय चरण नवंबर-दिसंबर 2026 और राष्ट्रीय स्तर का आयोजन जनवरी 2027 में प्रस्तावित है। जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

इच्छुक विद्यार्थी और शिक्षक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। समन्वयकों ने कोटपूतली क्षेत्र के सरकारी और निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में शामिल कराने की अपील की है, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को विज्ञान और नवाचार के राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके।

मेड़ता हत्याकांड में सभी आरोपी बरी, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की मांग

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटपूतली

वर्ष 2015 के बहुचर्चित मेड़ता हत्याकांड में विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने के बाद दलित समाज और सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। मेघवाल विकास समिति के जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुबेसिंह मोरोड़िया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को पत्र भेजकर फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में तत्काल अपील दायर करने की मांग की है।

घटना वर्ष 2015 में नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में हुई थी। मामले में अनुसूचित जाति वर्ग के छह लोगों की हत्या के आरोप लगे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने जांच के बाद 40 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी।

पांच अगस्त को विशिष्ट न्यायालय (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम), नागौर ने मामले में सभी 40 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अदालत के फैसले के बाद मोरोड़िया ने सरकार और जांच एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं तो छह लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले से पीड़ित परिवारों और आम लोगों के बीच न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

समिति के जिलाध्यक्ष ने कहा कि फैसले के बाद अनुसूचित जाति समाज में असुरक्षा और आक्रोश की भावना है। सरकार को मामले में कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी के साथ अपील दायर करनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद बनी रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते हाईकोर्ट में अपील दायर नहीं की गई तो सामाजिक संगठनों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। समिति ने राज्य सरकार से मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना देरी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है।

केशवाना औद्योगिक क्षेत्र की टूटी सड़कों से उद्योगपति और मजदूर परेशान

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बहरोड़

केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर उद्योगपतियों और कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। डामर उखड़ने के साथ जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे रोजाना आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक, कंटेनर और कर्मचारियों की बाइकें गुजरती हैं। उद्योग संचालकों के अनुसार गड्ढों में वाहनों के फंसने से कई बार ट्रकों के टायर क्षतिग्रस्त होने और माल को नुकसान पहुंचने की शिकायतें सामने आई हैं। दोपहिया वाहन चालक भी खराब सड़कों के कारण सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

बरसात के दौरान समस्या और गंभीर हो जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में छोटे-बड़े हादसे भी लगातार सामने आ रहे हैं।

कंपनी अधिकारियों ओमप्रकाश रोहिला और प्रदीप यादव ने कहा कि केशवाना औद्योगिक क्षेत्र राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में उद्योग संचालित हैं और सरकार को राजस्व भी मिलता है, लेकिन सड़क जैसी बुनियादी सुविधा की स्थिति खराब है।

मानसिंह शेखावत ने बताया कि सड़कों से उड़ने वाली धूल और गड्ढों के कारण कर्मचारियों का समय प्रभावित हो रहा है। इससे औद्योगिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है।

स्थानीय उद्योग संघ और मजदूर संगठनों ने प्रशासन तथा रीको से मांग की है कि औद्योगिक क्षेत्र की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का तत्काल सर्वे कराया जाए। खराब सड़कों की मरम्मत के साथ जरूरत वाले स्थानों पर नई सड़कों का निर्माण कराया जाए, ताकि उद्योगों और कर्मचारियों को आवागमन में राहत मिल सके।

भारत सितंबर में अफगानिस्तान से खेलेगा तीन मैचों की टी20 सीरीज; बांग्लादेश को क्यों लगा झटका!

मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को संयुक्त बयान जारी कर सीरीज की घोषणा की। सीरीज के तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला टी20 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को होगा। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच पूरी टी20 सीरीज पांच दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। इस एलान के साथ ही बांग्लादेश की भारत के खिलाफ सितंबर में प्रस्तावित लंबे समय से लंबित सफेद गेंद की सीरीज की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सीरीज पिछले साल टल गई थी। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण दोनों टीमों के बीच प्रस्तावित सीरीज को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद बांग्लादेश ने सितंबर में भारत के खिलाफ सीरीज की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, अब सितंबर के लिए भारत का कार्यक्रम अफगानिस्तान के खिलाफ तय हो गया है। ऐसे में बांग्लादेश की उस सीरीज को लेकर उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं।

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के सभी मुकाबले एक ही मैदान पर खेले जाएंगे। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम को तीनों मैचों की मेजबानी मिली है।

बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास को समर्थन देने और उसके खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर खेलने के मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय क्रिकेट टीमों को नियमित रूप से मजबूत विरोधी टीमों के खिलाफ खेलने और अनुभव हासिल करने का अवसर देता है। बीसीसीआई के मानद सचिव देवजीत सैकिया ने भी भारत-अफगानिस्तान क्रिकेट संबंधों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ वर्षों में नियमित द्विपक्षीय मुकाबले हुए हैं। सैकिया ने याद दिलाया कि भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले टेस्ट की मेजबानी की थी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच अलग-अलग फॉर्मेट में लगातार मुकाबले होते रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग: बाबर आजम की टॉप-10 में एंट्री

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा बुधवार को जारी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉप-10 में धमाकेदार एंट्री की है। बाबर को वेस्टइंडीज दौरे पर उनकी शानदार बल्लेबाजी का इनाम मिला है। वेस्टइंडीज दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 2 अर्धशतक की मदद से 193 रन बनाने वाले बाबर पांच स्थान की छलांग लगाते हुए आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं। शीर्ष 10 में बाबर एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के जो रूट, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, पांचवें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के टेंबा बावुमा, छठे स्थान पर श्रीलंका के कामिंडु मेंडिस, सातवें स्थान पर भारत के शुभमन गिल, आठवें स्थान पर न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र, और नौवें स्थान पर भारत के यशस्वी जायसवाल हैं। श्रीलंका के दिनेश चांदीमल एक स्थान नीचे खिसकते हुए टॉप-10 से बाहर हो गए हैं। वह 11वें वें स्थान पर हैं। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। शीर्ष 10 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस चौथे, दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन पांचवें, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड छठे, और दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा सातवें स्थान पर हैं। रबाडा को एक स्थान का फायदा हुआ है। पाकिस्तान के नोमान अली एक स्थान के नुकसान के साथ सातवें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड नौवें और ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन दसवें स्थान पर हैं।

टी20 सीरीज गंवाने के बावजूद पाकिस्तानी महिला खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार

दुबई। आईसीसी ने ताजा महिला टी20 प्लेयर रैंकिंग जारी की है। भले ही पाकिस्तान ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज 1-2 से गंवाई, लेकिन इसके बावजूद नाशरा संधू, शवाल जुल्फिकार और तुबा हसन की रैंकिंग में शानदार सुधार हुआ है। नाशरा संधू ने श्रीलंका के विरुद्ध तीसरे टी20 मैच में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। संधू गेंदबाजों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें पायदान पर पहुंच गई हैं। बाएं हाथ की स्पिनर ने इस सीरीज में 3 विकेट लिए और 6.72 का शानदार इकॉनमी रेट बनाए रखा। दूसरी तरफ, तुबा हसन गेंदबाजी रैंकिंग में तीन स्थान की बढ़त के साथ 48वें नंबर पर पहुंच गई हैं। श्रीलंकाई टीम से, कप्तान चामरी अट्टापट्टू अपनी टीम की ऐतिहासिक सीरीज जीत में योगदान देने के बाद 5 स्थान ऊपर चढ़कर 36वें नंबर पर पहुंच गईं। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने साल 2014 के बाद पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय टी20 सीरीज अपने नाम की है, जिसमें इमेशा दुलानी की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड जीता। दाएं हाथ की बल्लेबाज ने 61.50 की औसत से 123 रन बनाए और टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर 22वें नंबर पर पहुंच गईं। दुलानी ने 31 जुलाई को शुरुआती मैच में शानदार शुरुआत की और मेजबान टीम को छह विकेट और छह गेंदें शेष रहते हुए 177 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की।

आखिरकार जॉर्जिना के हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो

10 साल डेट करने के बाद गुपचुप की शादी

लिस्बन (एजेंसी)। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब आधिकारिक तौर पर शादीशुदा हो गए हैं। 41 वर्षीय पुर्तगाली सुपरस्टार ने अपनी लंबे समय से पार्टनर रहीं जॉर्जिना रोड्रिगेज को अपना जीवनसाथी बना लिया है। दोनों ने मंगलवार, 11 अगस्त को पुर्तगाल के कास्काइस में एक बेहद निजी सिविल सेरेमनी में शादी की। खास बात यह रही कि इस मौके पर उनके पांच बच्चे भी मौजूद थे।

तीन अक्षरों में दी शादी की खबर

शादी को पूरी तरह निजी रखने वाले रोनाल्डो ने किसी बड़े एलान या भव्य तस्वीरों के बजाय सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को खुशखबरी दी। उन्होंने अपनी और जॉर्जिना की हाथों की तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों की उंगलियों में मैचिंग गोल्ड वेडिंग रिंग नजर आ रहे थे। इस तस्वीर के साथ रोनाल्डो ने सिर्फ 'ष्टत्न' लिखा। और साथ ही दिल भी बनाया। स्पैनिश स्पोर्ट्स डेली मार्का और सऊदी अरब के अखबार गल्फ न्यूज ने भी शादी की पुष्टि की। बताया गया कि यह समारोह बेहद निजी और अंतरंग था तथा इसमें कपल के पांच बच्चे शामिल हुए।

10 साल से ज्यादा समय से साथ हैं

रोनाल्डो और जॉर्जिना का रिश्ता करीब एक दशक पुराना है। दोनों की मुलाकात 2016 में मैड्रिड में हुई थी। उस समय जॉर्जिना एक गुच्ची स्टोर में काम करती थीं। उन्होंने बाद में बताया था कि रोनाल्डो से पहली मुलाकात के दौरान उनके पेट में 'तितलियां उड़ने' जैसा एहसास हुआ था।इसके बाद दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे सार्वजनिक हुआ और दोनों ने एक साथ परिवार बसाया। रोनाल्डो के फुटबॉल करियर के स्पेन, इटली, इंग्लैंड और सऊदी अरब तक पहुंचने के दौरान जॉर्जिना लगातार उनके साथ रहीं।

2025 में हुई थी सगाई

शादी से करीब एक साल पहले जॉर्जिना ने अगस्त 2025 में सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की जानकारी दी थी। उन्होंने रोनाल्डो के साथ हाथ की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उनकी बड़ी डायमंड रिंग नजर आई थी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, यस आई डू इन दिस एंड इन ऑल माई लाइव्स।

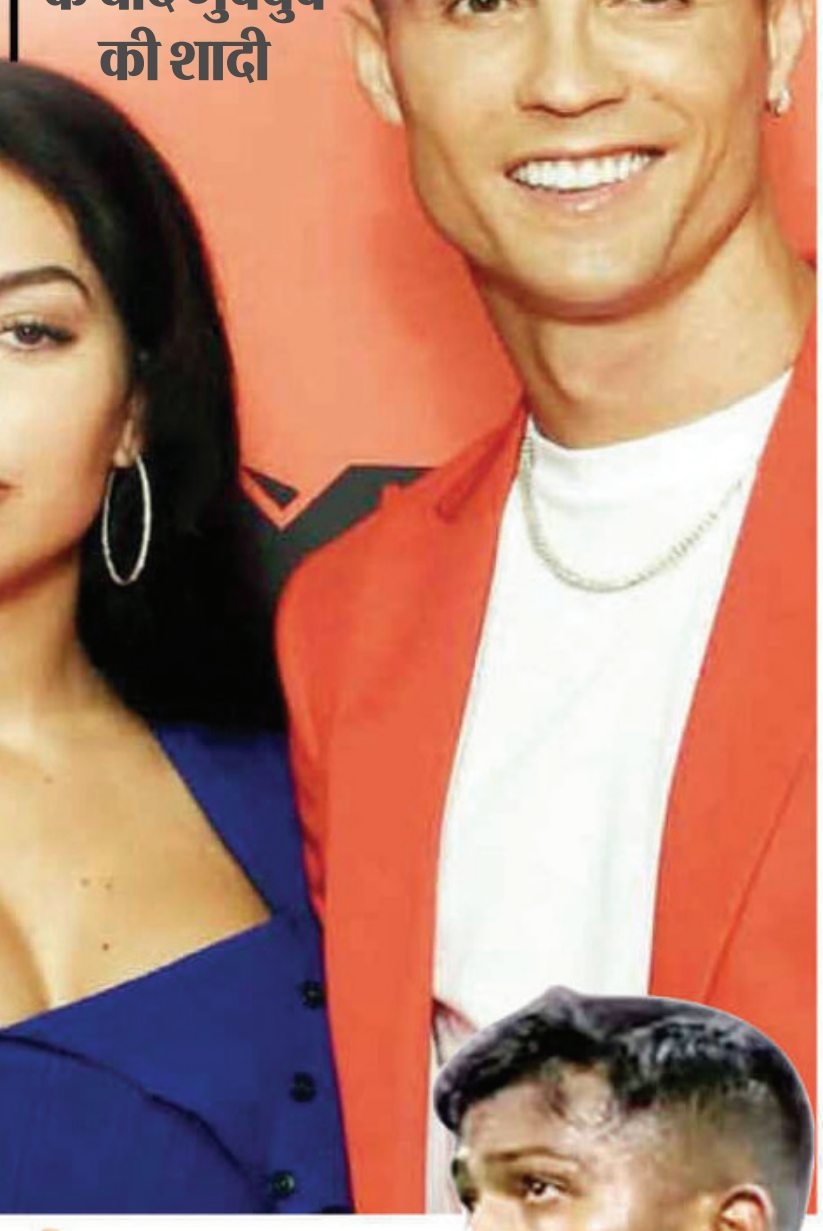

गुजरात में लौटना चाहते थे हार्दिक... पर जीटी ने बंद किए वापसी के सभी रास्ते!

पांड्या ने ऐसी क्या रख दी थी मांग?

कई टीमों ने हार्दिक में दिखाई दिलचस्पी

मुंबई। हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के साथ भविष्य एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इसी बीच खबर है कि भारतीय ऑलराउंडर ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस में लौटने की कोशिश की थी। गुजरात भी उनकी वापसी के विचार के खिलाफ नहीं था, लेकिन कप्तानी को लेकर रखी गई पांड्या की मांग ने पूरी बातचीत को खत्म कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पांड्या ने अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के साथ वापसी को लेकर बातचीत की थी। पांड्या और गुजरात, दोनों ही इस संभावना के लिए तैयार थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि पांड्या ने गुजरात टाइटंस को 2022 में उसके पहले ही सीजन में आईपीएल चैंपियन बनाया था। हालांकि, वापसी के लिए पांड्या की एक अहम शर्त थी। वह चाहते थे कि गुजरात टाइटंस में लौटने के साथ उन्हें दोबारा टीम की कप्तानी भी सौंपी जाए।

कप्तानी की मांग बनी डील ब्रेकर

रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक की कप्तानी की मांग पर गुजरात टाइटंस ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फ्रेंचाइजी ने मौजूदा कप्तान शुभमन गिल से भी इस संभावित बदलाव को लेकर बात की थी। गिल इस बात के लिए तैयार बताए गए कि फ्रेंचाइजी हार्दिक को वापस ट्रेड कर सकती है। लेकिन जब पांड्या की ओर से कप्तानी को वापसी की शर्त के तौर पर रखा गया, तो गुजरात टाइटंस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 'फ्रेंचाइजी उनके लौटने के पक्ष में थी। उन्होंने अपने कप्तान शुभमन गिल से भी इस बारे में बात की थी और वह भी इसके लिए तैयार थे। लेकिन जब कप्तानी की शर्त सामने आई, तो सभी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।'

मुंबई इंडियंस में भी भविष्य पर सवाल

हार्दिक की गुजरात में वापसी की कोशिश ऐसे समय में सामने आई है, जब मुंबई इंडियंस में उनके भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का 2026 आईपीएल सीजन निराशाजनक रहा। टीम ने 14 में से सिर्फ चार मैच जीते और अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही। पांड्या का मुंबई के प्रशंसकों के साथ रिश्ता भी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने 2021 सीजन के बाद मुंबई का साथ छोड़ा था और 2024 में टीम में वापसी की। वापसी के बाद उन्हें रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई इंडियंस का टीम मैनेजमेंट पांड्या को कप्तान के तौर पर बनाए रखने को लेकर उत्सुक नहीं था। खराब सीजन के बाद टीम में उनकी भूमिका को लेकर भी विचार किया जा रहा था। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स समेत कई फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को लेकर मुंबई इंडियंस से पूछताछ की है।

पांड्या के प्रवक्ता ने क्या कहा

हालांकि, हार्दिक पांड्या के प्रवक्ता ने इन खबरों पर अलग रुख रखा है। उन्होंने कहा कि ऑलराउंडर ने ट्रांसफर या ट्रेड को लेकर किसी भी फ्रेंचाइजी से सीधे बातचीत नहीं की है। प्रवक्ता के मुताबिक, 'हार्दिक पांड्या ने ट्रांसफर, ट्रेड या किसी अन्य तरीके से किसी भी फ्रेंचाइजी से सीधे बातचीत नहीं की। अगर उनसे कोई संपर्क किया गया है, तो वह मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के जरिए किया गया है।' इस तरह गुजरात टाइटंस में वापसी की चर्चा के बावजूद कप्तानी की शर्त के कारण यह संभावित डील आगे नहीं बढ़ सकी।

संन्यास के बावजूद श्रीलंका दौरे पर क्यों गए अजिंक्य रहाणे

कोलंबो। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे अब मैदान के अंदर नहीं, बल्कि कमेंट्री बॉक्स से टेस्ट क्रिकेट का अनुभव साझा करते नजर आएंगे। रहाणे भारत के आगामी श्रीलंका दौरे पर टेस्ट कमेंट्री में डेब्यू करने वाले हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी और इसी सीरीज के साथ रहाणे कमेंट्री की दुनिया में अपनी नई पारी शुरू करेंगे। वह ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स के कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। रहाणे का यह कदम उनके करीब 18 साल लंबे फर्स्ट क्लास करियर के खत्म होने के कुछ ही समय बाद आया है। अपने करियर के बड़े हिस्से में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के मुश्किल माहौल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। अब 37 साल की उम्र में रहाणे पांच दिन तक चलने वाले टेस्ट मैच को एक खिलाड़ी के बजाय कमेंटेटर के नजरिए से देखेंगे। वह मैच के दौरान रणनीतिक फैसलों, महत्वपूर्ण पलों और मुकाबले की दिशा बदलने वाले घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 5,077 रन बनाए। उनके नाम 12 शतक और 26 अर्धशतक हैं। अलग-अलग परिस्थितियों में टेस्ट क्रिकेट खेलने और दबाव के बीच प्रदर्शन करने का उनका अनुभव कमेंट्री के दौरान उनके लिए अहम साबित हो सकता है। मैदान पर लंबे समय तक खेलने के बाद अब वह अपने अनुभव के जरिए दर्शकों को टेस्ट क्रिकेट की बारीकियां समझाने की कोशिश करेंगे।

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए श्रीलंकाई टीम घोषित

कोलंबो। भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के लिए श्रीलंकाई टीम का एलान हो गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम का एलान किया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोसन डिकवेला करीब तीन साल बाद श्रीलंका की टेस्ट टीम में लौटे हैं। 33 वर्षीय डिकवेला ने पिछली बार 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा। वहीं, दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंका के स्क्वॉड में अनकैप्ड ऑफ स्पिनर केशरा नुवांथा और अनकैप्ड टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पसिंदु सूरियाबंदर को भी जगह मिली है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका की भी टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने अब तक सिर्फ एक टेस्ट खेला है। वहीं, कुसल मेंडिस और पाथुम निसांका फिलहाल पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं।डिकवेला की वापसी की सबसे बड़ी वजह कुसल मेंडिस का टीम से बाहर होना है। मेंडिस हैमस्ट्रिंग चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वहीं पाथुम निसांका भी कलाई की सर्जरी से उबर रहे हैं और टीम में नहीं हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11 घोषित

डार्विन। ऑस्ट्रेलिया गुरुवार से बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज से एक साल में 20 टेस्ट मैच खेलने के अपने व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इस मैच से 2003 के बाद टेस्ट क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वापसी भी होगी। बांग्लादेश का दो दशकों से अधिक समय में ऑस्ट्रेलिया का यह पहला टेस्ट दौरा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 घोषित कर दी है।ऑस्ट्रेलिया का अगले 12 महीने का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। इस दौरान वह 20 टेस्ट मैच खेलेगा, जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड के दौरे भी शामिल हैं। अगर वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है तो इन मैच की संख्या 21 हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसके बाद वह चार टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया को इसके बाद भारत में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वह मार्च में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगा जो दोनों देशों के बीच टेस्ट मैचों की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा।

छात्रों और अभिभावकों ने नैनवां-बूंदी मार्ग 3 घंटे जाम किया

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बूंदी

बूंदी के नैनवां ब्लॉक स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाढून के छात्रों और अभिभावकों ने बुधवार को शिक्षकों की कमी के विरोध में नैनवां-बूंदी स्टेट हाईवे जाम कर दिया। चंदनपुरा चौराहे के पास यह प्रदर्शन करीब तीन घंटे तक चला। अभिभावक लोकेश बंजारा ने बताया कि राज्य सरकार ने 2022-23 में स्कूल को 10वीं से 12वीं तक क्रमोन्नत किया था। वर्तमान में 12 कक्षाओं के लिए केवल पांच शिक्षक हैं, जबकि नियमानुसार 17 से 18 शिक्षकों की आवश्यकता है। स्कूल में लगभग 300 छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं। पहले यह संख्या 450 थी, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण कई छात्र टीसी कटवाकर अन्य स्कूलों में चले गए। बंजारा के अनुसार उन्होंने जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन कोई अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया। इस अनदेखी के कारण उन्हें जाम लगाने का कदम उठाना पड़ा। जाम के कारण नैनवां से बूंदी आने-जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारी छात्र और अभिभावक हाथों में तख्तियां लिए 'शिक्षक दो, अन्याय नहीं सहेंगे' जैसे नारे लगा रहे थे। सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। नैनवां ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) ओम प्रकाश बुनकर ने बताया कि स्कूल 2022-23 में क्रमोन्नत हुआ था और वर्तमान में चार अध्यापक व एक अन्य स्टाफ सदस्य कार्यरत हैं। बुनकर ने ग्रामीणों को संतुष्ट करने के लिए तत्काल दो शिक्षक नियुक्त करने की बात कही। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कुछ दिनों बाद दो और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस दौरान मोडासा के प्रिंसिपल कुलदीप सुमन और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश मीणा भी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात सुचारु हो सका।

मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक दर्जा नहीं: कांग्रेस का विरोध

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा डूंगरपुर

डूंगरपुर में कांग्रेस ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। बुधवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक गणेश घोघरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक रैली निकाली। बारिश के बीच यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से उनके बयान पर माफी मांगने की मांग की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए। यहां से बड़ी संख्या में बाइक पर सवार होकर रैली रवाना हुई। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि मानगढ़ धाम केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि 1500 से अधिक भील आदिवासियों की शहादत का प्रतीक है। उन्होंने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने संसद में कहा था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। घोघरा ने बताया कि आदिवासी समाज लंबे समय से यह मांग कर रहा है। घोघरा ने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बावजूद इसे लेकर 'भेड़चाल' और 'विदेशी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। कांग्रेस ने मांग की कि मदन राठौड़ अपने बयान पर आदिवासी समाज से माफी मांगें। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

जोधपुर में बस में आग लगाने वाले दो बदमाश गिरफ्तार: दोनों आरोपी हिस्ट्रीशीटर हैं

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा जोधपुर

जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने बस में आग लगाने और मारपीट का मामले में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दोनों आरोपी मोस्ट वांटेड हिस्ट्रीशीटर हैं। आरोपियों की पहचान भूपेंद्रसिंह (29) पुत्र भरतसिंह निवासी गिंगाला, थाना खेड़ापा और हीरसिंह (30) पुत्र नैनसिंह निवासी श्री मोहनगढ़, जिला जैसलमेर के रूप में हुई है। आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अब तक एक दर्जन से ज्यादा बसों को आग के हवाले कर चुके हैं। बता दें कि 4 अगस्त की रात चौपासनी स्कूल के पास खड़ी बस को आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था। घटना के वक्त बस के अंदर सो रहे ड्राइवर विक्रम सिंह ने जैसे-तैसे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। बस मालिक महिपाल सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर थानाधिकारी रवींद्रपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने चौपासनी और आसपास के इलाके के करीब 200 ष्टष्ट्रङ्क कैमरों के फुटेज खंगाले और आरोपियों का रूटमैप तैयार किया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी भूपेंद्रसिंह पुलिस थाना खेड़ापा का हिस्ट्रीशीटर है। इसके खिलाफ 27 मामलों में चालान पेश हो चुका है और यह 5 मुकदमों में वांटेड चल रहा था। बाप पुलिस थाने से इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं दूसरा आरोपी हीरसिंह पुलिस थाना श्री मोहनगढ़ जैसलमेर का हिस्ट्रीशीटर है। इसके खिलाफ 13 मामलों में चालान हो चुका है और यह भी 5 मामलों में वांटेड चल रहा था।

सिंगला बांध से किसानों की ट्रैक्टर रैली, अजमेर में रोकी: कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे; बैरिकेडिंग्स लगाई, पुलिस जाब्ता तैनात

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा किशनगढ़

अजमेर के रूपनगढ़ से ट्रैक्टर रैली लेकर निकले किसानों को अजमेर में एंट्री से पहले ही रोक लिया गया है। किसान सिंगला बांध के भूमि अवार्ड निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस ने अजमेर में एंट्री से पहले ही लोहागल के पास पुलिस जाब्ता तैनात कर उनको रोक लिया है। ट्रैक्टर रैली में करीब 96 ट्रैक्टर हैं और रैली की जानकारी मिलते ही पुष्कर की पूर्व विधायक नसीम अख्तर इंसाफ भी मौके पर पहुंच गई है। मौके पर पहुंचे रूपनगढ़ एसडीएम रामकुमार टाडा ने किसानों के साथ बैठ कर वार्ता शुरू की है। रूपनगढ़ एसडीएम रामकुमार टाडा ने वार्ता के लिए 20 किसानों को शास्त्री नगर थाने में बुलाया है। फिलहाल, किसानों और एसडीएम के बीच वार्ता जारी है। मिली जानकारी के अनुसार, रूपनगढ़ के सिंगला बांध पर पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों ने बुधवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर अजमेर कूच किया। सिंगला बांध से 96 ट्रैक्टरों के साथ किसान अजमेर कलक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए।

रैली के अजमेर पहुंचने से पहले ही शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर किसानों को रोक दिया। किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए शास्त्रीनगर थाने के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर करीब 100 पुलिसकर्मियों के साथ एक डंपर और एक जेसीबी भी खड़ी की गई। पुलिस ने ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद मौके पर किसानों और पुलिस के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। किसान सिंगला बांध पर पिछले 20 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं होने के कारण अब ट्रैक्टर रैली के माध्यम से प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय किया गया।

ये है मामला

सिंगला बांध के भराव क्षेत्र की कृषि भूमि के अवार्ड को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन अब आक्रोश के चरम पर पहुंच गया है। मामले के अनुसार वर्ष 1993-94 में सींगला बांध का निर्माण किसानों और क्षेत्र की जलापूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। उसी समय भराव क्षेत्र की करीब 2500 बीघा भूमि सिंचाई विभाग के नाम अवार्ड की गई और प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा भी निर्धारित किया गया। वर्षों तक किसानों को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिली और भूमि से जुड़े नामांतरण, विरासत, खरीद-फरोख्त तथा केसीसी जैसे कार्य सामान्य रूप से चलते रहे। हाल ही में मोरसागर बांध निर्माण और आनासागर का अतिरिक्त पानी सिंगला बांध तक लाने की प्रक्रिया शुरू होने के दौरान किसानों को जानकारी मिली कि उनकी भूमि पहले ही अवार्ड हो चुकी है। इसके बाद प्रभावित किसानों ने 25 जुलाई से सिंगला बांध पर धरना शुरू किया।

मंत्री सुरेश रावत ने भी की थी चर्चा

2 अगस्त को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से करीब दो घंटे तक चर्चा की और भराव क्षेत्र की भूमि का अवार्ड निरस्त कराने का मामला मंत्रिमंडल में रखने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने नामांतरण, विरासत और केसीसी जैसी प्रक्रियाएं पूर्ववत जारी रखने की बात भी कही। मंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने आंदोलनकारियों द्वारा दिए गए दो विरासत प्रकरणों की प्रक्रिया शुरू कर उनका निस्तारण भी कर दिया। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि जब तक भूमि अवार्ड निरस्त करने सहित सभी मांगों पर ठोस और लिखित समाधान नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

स्कूल में छात्र के सीने में घुसा तीर: तीरंदाजी अभ्यास के दौरान 8वीं का स्टूडेंट्स हुआ घायल

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा डूंगरपुर

डूंगरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा में मंगलवार शाम तीरंदाजी अभ्यास के दौरान 8वीं कक्षा के एक छात्र के सीने में तीर घुस गया। तलैया, बिछीवाड़ा निवासी छात्र विकास ननोमा तीरंदाजी कोर्ट में अभ्यास कर रहे बच्चों के बीच अचानक पहुंच गया था, तभी यह हादसा हुआ। तीर लगने के बाद विकास ने उसे तुरंत हाथ से निकाल लिया, लेकिन उसका आगे का नुकीला लोहे का टुकड़ा सीने में ही फंसा रह गया। स्कूल स्टाफ ने तुरंत घायल छात्र को सागवाड़ा सरकारी अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी छात्र के परिजनों और जिला प्रशासन को भी दी गई। सागवाड़ा अस्पताल से छात्र को एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां इलाज संभव नहीं हो सका। इसके बाद उसे मंगलवार रात में ही उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने उदयपुर प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया था, जिससे अस्पताल में डॉक्टरों की टीम तैयार थी। छात्र के अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। रात करीब 2 बजे डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर विकास के सीने से तीर का नुकीला लोहे का टुकड़ा सफलतापूर्वक निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद छात्र की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और

वह होश में है। परिजन भी उदयपुर पहुंच गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अमिल मीणा ने बताया कि अगले महीने से तीरंदाजी की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होनी हैं, जिसके लिए छात्र तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान विकास बीच में आ गया और उसे तीर लग गया। उन्होंने पुष्टि की कि उदयपुर आरएनटी में ऑपरेशन के बाद विकास की तबीयत ठीक है और उसमें सुधार हो रहा है।

पांच टीचर के भरोसे 600 बच्चे, 11 पोस्ट खाली: छात्रों ने स्कूल गेट पर लगाया ताला, ग्रामीणों के साथ 4 घंटे किया प्रदर्शन

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा जालोर

जालोर में बागोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवापुरा ध्वेछा में चार साल से 11 शिक्षक पद खाली हैं। स्कूल में 600 बच्चों की पढ़ाई सिर्फ 5 शिक्षकों के भरोसे चल रही है। ऊपर से गणित शिक्षक मोतीराम को चुनाव शाखा में डेपुटेशन पर लगा दिया गया। इससे नाराज छात्रों ने बुधवार सुबह स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गणित शिक्षक का डेपुटेशन रद्द करने और गुरुवार तक 2 नए शिक्षक लगाने का भरोसा दिया, इसके बाद छात्रों ने ताला खोल दिया। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि चेतनराम ने बताया कि स्कूल में 12वीं कक्षा तक करीब 600 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यालय में शिक्षकों के कुल 16 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पिछले चार साल से 11 पद खाली पड़े हैं। वर्तमान में सिर्फ पांच शिक्षक ही कार्यरत हैं। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए स्कूल में कार्यरत पांच शिक्षकों में से गणित शिक्षक मोतीराम को चुनाव शाखा में डेपुटेशन पर लगा दिया गया। इससे विद्यार्थियों की परेशानी और बढ़ गई। छात्रों का कहना था कि पहले ही शिक्षकों की कमी है और ऐसे में गणित शिक्षक को

भी स्कूल से हटाने पर पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। शिक्षकों की नियुक्ति और गणित शिक्षक का डेपुटेशन निरस्त करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने सुबह करीब 7 बजे स्कूल गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद छात्र-छात्राएं गेट के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। कई अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए और विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर करीब 11 बजे बागोड़ा सीबीओ जीवाराम, एसडीएम लाखाराम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से समझाइश की और उनकी मांगों को सुना। अधिकारियों ने गणित शिक्षक मोतीराम का चुनाव शाखा में किया गया डेपुटेशन निरस्त करने और गुरुवार तक स्कूल में दो शिक्षकों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया।

बारां में बारिश का कहर: तलेटी क्षेत्र के दर्जनों गांव कटे

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बारां

प्रदेश में हो रही लगातार बारिश का असर बारां जिले के शाहाबाद उपखंड के तलेटी क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की नदी-नाले उफान पर हैं। इसके कारण तलेटी क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति चौराखाड़ी गांव के पास बह रही नदी की है। यहां पुल-पुलिया नहीं होने के कारण ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। कई लोग पैदल तो कुछ ग्रामीण बाइक और अन्य साधनों से तेज बहाव के बीच नदी पार कर रहे हैं। नदी पर तेज बहाव के साथ करीब दो फीट तक पानी की चादर चल रही है। इसके बावजूद ग्रामीण इसी तेज बहाव के बीच एक छोर से दूसरे छोर तक जाने को मजबूर हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पार करते समय पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से नदी-नालों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं और न ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मौके पर न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही कोई सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया है। ऐसे में तेज बहाव के बीच लोगों का नदी पार करना लगातार खतरे को न्योता दे रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षा इंतजाम करने और आवागमन के लिए स्थायी समाधान की मांग की है।

महिला मरीजों को ड्रिप चढ़ाने के बाद एलर्जी: ड्रिप के पूरे बैच को किया फ्रिज

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटा

कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हॉस्पिटल में भर्ती महिला मरीजों को ड्रिप (आईवी फ्लूइड) चढ़ाए जाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन और सेहत बिगड़ने की बात सामने आई। इसके बाद हॉस्पिटल के ड्रग वेयर हाउस ने संबंधित ड्रिप के पूरे बैच को तत्काल प्रभाव से होल्ड (फ्रीज) कर दिया गया है। सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए है। बता दें कि सोमवार देर रात ड्रिप चढ़ाए जाने के कुछ देर बाद ही चार पांच महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी। वहीं पिछले दो दिन में तीन प्रसुताओं की मौत भी हो चुकी है। मरीजों की शिकायत सामने आने के बाद हॉस्पिटल अधीक्षक की ओर से ड्रग विभाग को पत्र लिखा। पत्र में बताया कि मरीजों को दी जा रही 'कम्पाउंड सोडियम लेकटेट 500 एमएल (रिंगर लेक्टेट) ड्रिप से एलर्जिक रिएक्शन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। यह ड्रिप अलबर्ट डेविड लिमिटेड कंपनी की ओर से दी गई थी ड्रग वेयर हाउस के प्रभारी डॉ. सुशील सोनी ने बताया कि जेके लोन हॉस्पिटल से शिकायत पत्र मिलने के बाद तुरंत मुख्यालय (जयपुर) को अवगत कराया गया। मुख्यालय के निर्देशानुसार उक्त बैच को पूरी तरह से होल्ड कर दिया गया है। ड्रिप के सैंपल जांच के लिए जयपुर लैब भेजे गए हैं। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए और वैकल्पिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ड्रग विभाग ने तुरंत कदम उठाए हैं।

फाइनेंसर हत्याकांड का मुख्य आरोपी एमपी से गिरफ्तार: 70 लाख के लालच में मारा था

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा भीलवाड़ा

भीलवाड़ा के फाइनेंसर शोभालाल जैन हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोशन गुर्जर को पुलिस ने मध्यप्रदेश के सागर जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के बैंक खाते में करीब 70 लाख रुपए होने की जानकारी उसके मुनीम को थी और इसी रकम व संपत्ति के लालच में उसने हत्या की साजिश रची। रोशन ने अपने परिचित को 10 लाख रुपए का लालच देकर साथ मिलाया। दोनों ने पहले भी हत्या की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद धार्मिक यात्रा के बहाने शोभालाल जैन को अपने साथ ले गए और लौटते समय उनकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। मामले में मुनीम के साथी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पुलिस उससे हत्या की साजिश, वारदात में इस्तेमाल साधनों और लूटे गए सामान को लेकर पूछताछ कर रही है। बागोर थाना प्रभारी ने बताया - फाइनेंसर शोभालाल जैन (78) की हत्या के मामले में आरोपी नारायण सरगरा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मुख्य आरोपी रोशन गुर्जर की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए डीएसटी, साइबर सेल

और बागोर थाना पुलिस की टीम बनाई गई थी। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार दबिश के बाद पुलिस टीम आरोपी तक पहुंची और उसे चंद्रपुर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी रोशन गुर्जर पुत्र सुखदेव, उम्र 34 साल, अड़सीपुरा, थाना बागोर, जिला भीलवाड़ा का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि मृतक के बैंक खाते में करीब 70 लाख रुपए होने की जानकारी उसके मुनीम रोशन गुर्जर को थी। पुलिस के मुताबिक इसी रकम और संपत्ति के लालच में रोशन ने हत्या की साजिश रची।

एक ही दिन में उठी 6अर्थियां, रो पड़ा पूरा धौलपुर: एक घर में नहीं बची कोई महिला

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा धौलपुर

धौलपुर में बुधवार को एक ही दिन में एक साथ 6 अर्थियां उठी। इससे पूरा शहर रो पड़ा। यह अर्थियां चंबल नदी किनारे स्थित मुक्तिधाम पहुंचीं तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। पूरे शहर में शोक का माहौल छा गया। एक घर तो अब कोई महिला ही नहीं बची है। अंतिम संस्कार ने दौरान बेटे ने पिता को कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के इस दृश्य ने पूरे शहर को गम में डुबो दिया। इसके साथ ही शहर के लोगों को 29 साल पुराना हादसा फिर याद आ गया, जिसमे एक साथ 6 लोगों की मौत हुई थी और तब भी 6 लोगों की एक साथ अर्थियां उठी थी। दरअसल मंगलवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसों में धौलपुर में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहे पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र के त्रिवेदी परिवार की कार डंपर से टकरा गई। इस हादसे में कपड़ा व्यवसायी सुनील त्रिवेदी की पत्नी सोमा (65), बेटा अंकुर (42) और बहू अर्चना (40) की जान चली गई। तीनों के शव पोस्टमॉर्टम के बाद देर रात धौलपुर लाए गए। बुधवार सुबह त्रिवेदी परिवार के घर से जब तीनों की अंतिम यात्रा निकली, तो बड़ी संख्या में रिश्तेदार और परिचित वहां मौजूद थे। चंबल मुक्तिधाम में

सुनील त्रिवेदी ने अपनी पत्नी सोमा को मुखाग्नि दी। उनके छोटे बेटे रत्नेश ने अपने भतीजे अंश के साथ अंकुर और अर्चना का अंतिम संस्कार किया। धौलपुर के इतिहास में 12 अक्टूबर 1997 का दिन आज भी एक दर्दनाक हादसे के रूप में याद किया जाता है। जयपुर के पास टाटा सूमो पलटने से हनुमान तिराहे पर रहने वाले तिवारी परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के करीब 29 साल बाद मंगलवार को धौलपुर ने फिर वैसा ही कलेजा चीर देने वाला दृश्य देखा।

यूपीः आकाश आनंद ने राहुल-अखिलेश को कहा 'अंकल', अखिलेश का पलटवार- हमसे कुछ न कहलवाओ तो अच्छा..

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा लखनऊ

उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर जमकर हमला बोला। भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों को 'अंकल' कहकर संबोधित किया। अखिलेश यादव द्वारा बसपा प्रमुख मायावती को 'बुआ' कहे जाने के संदर्भ में जब आकाश आनंद से सवाल उठा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अखिलेश यादव को भैया नहीं मानेंगे। वह उन्हें अंकल ही कहेंगे। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि 'राहुल अंकल' अक्सर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और दलित अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी वही नीतियाँ लागू हैं जिनका वे विरोध करते हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता के लिए कांग्रेस और भाजपा में कोई खास फर्क नहीं है। बसपा नेता आकाश आनंद के सपा अध्यक्ष को अंकल कहे जाने के सवाल अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहस का मुद्दा नहीं है। हमसे कुछ न कहलवाओ। हमारे संबंध बहुतों से अच्छे से रहे हैं। मुकाबला उनसे हैं जो दिल्ली और यूपी में बैठे हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए धन ही धर्म है। भाजपा अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी पर जवाब नहीं दे रही है। सरकार चर्चा से भाग रही है।अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा-परीक्षा और श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है। हम लोग चाहते है कि दोनों मुद्दों पर चर्चा हो। सरकार दिल्ली में छात्रों पर हुई बर्बरता पर जवाब दे। अखिलेश ने मंगलवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के संगी-साथी अंडरग्राउंड और गैर पंजीकृत लोगों के तार शिक्षा-परीक्षा और राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी से जुड़े है।

'मैं आज भी मां की कमी महसूस करता हूं', पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की आत्मकथा के विमोचन पर भावुक हुए पीएम

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और उनके जीवन संघर्ष को प्रेरणा बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां का भी जिक्र किया और उनका जिक्र कर भावुक भी हुए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की इस आत्मकथा का शीर्षक 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स' है। आत्मकथा में रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी है। इसमें उनके शुरुआती वर्षों से लेकर सार्वजनिक जीवन और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा तक के अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का ब्योरा है। इस किताब के विमोचन के अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा, 'राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन और उनका स्नेह, उनकी आत्मीयता मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही।' पीएम मोदी ने कहा, 'मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज की धरोहर बनेगी।' इसके बाद पीएम मोदी ने कहा, 'रामनाथ कोविंद ने छोटी सी उम्र में मां को खो दिया। मैं तो भाग्यशाली रहा हूं कि मेरी मां 100 वर्ष से अधिक जीवित रहीं और मुझे आशीर्वाद देती रहीं, इसके बावजूद मैं मां की कमी महसूस करता हूं। ऐसे हालात में कोई भी टूट सकता है, लेकिन रामनाथ कोविंद को उन मुश्किल हालात ने और मजबूत बनाया।' पीएम मोदी ने कहा कि हमें भविष्य में रामनाथ कोविंद जैसे अनेकों युवा चाहिए, जो परेशानियों से परास्त न हों, जो मुश्किलों से मायूस न हों बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखें। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वाले बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

राष्ट्रपति ने 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026' को मंजूरी दे दी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। इसके साथ ही, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। इस संशोधन से मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 37 और न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकेगी। उम्मीद है कि इससे मामलों के बढ़ते बैकलॉग और संवैधानिक पीठों के गठन के कारण नियमित सुनवाई पर पड़ने वाले असर को कम करने में मदद मिलेगी। लोकसभा ने 3 अगस्त को इस बिल को मंजूरी दी। इसके बाद, राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पहल पर आगे बढ़ा। कानून मंत्री के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 11 मई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था। चीफ जस्टिस ने अपने पत्र में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों की बढ़ती संख्या के कारण रोजाना बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा करना जरूरी हो गया है। हालांकि, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच (संविधान पीठ) के गठन से नियमित मामलों की सुनवाई पर असर पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में शामिल जजों को नियमित सुनवाई से अलग होना पड़ता है। उन्होंने हाल ही में बनी नौ-जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का भी जिक्र किया, जो सबरीमाला मामले से जुड़े एक रेफरेंस पर सुनवाई कर रही है। ऐसे मामलों से नियमित मामलों की सुनवाई और निपटारे की रफ्तार पर असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था।

रूस-यूक्रेन के बीच अरबों डॉलर के विवाद को सुलझाएंगे पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़, पुतिन ने दी बड़ी जिम्मेदारी

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा मॉस्को

रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को निवेश संधि विवाद में अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। यह विवाद यूक्रेन के सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ओशचाडबैंक द्वारा दायर किया गया है। ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। इस विवाद की सुनवाई 1998 की यूक्रेन-रूस द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत तीन सदस्यीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा की जा रही है। कोस्टा रिका की मध्यस्थ और पूर्व व्यापार मंत्री डियाला जिमेनेज को दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं, ग्रीक मध्यस्थ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर स्टावरोस ब्रेकोलाकिस को ओशचाडबैंक द्वारा नियुक्त किया गया है, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ को रूस द्वारा नियुक्त किया गया है। ओशचाडबैंक का दावा डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया में मौजूद उसकी संपत्तियों और गतिविधियों से संबंधित है। यूक्रेनी सरकारी बैंक का कहना है कि यूक्रेन में 2022 में रूस के आक्रमण के बाद रूसी सैन्य कार्रवाइयों ने इन क्षेत्रों में अपनी संपत्तियां खो दी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह दावा करोड़ों डॉलर का है। बार एंड बेंच के अनुसार, ओशचाडबैंक ने जुलाई 2025 में रूस को विवाद का नोटिस भेजा था, जिसका कथित तौर पर कोई जवाब नहीं मिलने के बाद बैंक ने मध्यस्थता प्रक्रिया की शुरुआत की। यह कार्यवाही रूसी संघ की सरकार और यूक्रेन के मंत्रिमंडल के बीच 1998 में हुए निवेश के प्रोत्साहन और पारस्परिक संरक्षण समझौते के तहत शुरू की गई है। यह विवाद ओशचाडबैंक की उस पिछली मध्यस्थता प्रक्रिया से अलग है जो 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसकी गतिविधियों और संपत्तियों को लेकर शुरू हुई थी। उस पुराने मामले में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत गठित ट्रिब्यूनल ने रूस को अवैध अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार ठहराया था और ओशचाडबैंक को ब्याज और मध्यस्थता लागत के साथ लगभग 1.1 अरब डॉलर का मुआवजा दिया था। हालांकि, रूस ने उस कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने लागू मध्यस्थता नियमों के तहत अपना काम जारी रखा था।

चंद्रचूड़ ने पहले ठुकरा दिया था रूस का प्रस्ताव

जस्टिस चंद्रचूड़ ने इससे पहले जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरशॉल डी और यूक्रेनी सरकारी ऊर्जा कंपनी उक्रेनर्गो से जुड़े संधि विवादों में रूस की तरफ से मध्यस्थ बनने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। उन्हें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा विंटरशॉल की कार्यवाही में नियुक्ति प्राधिकारी भी नामित किया गया था। हालांकि, रूस की तरफ से किए गए संपर्क का खुलासा करने के बाद वे इस भूमिका से हट गए थे। ओशचाडबैंक मामले में रूस के मध्यस्थ के रूप में उनकी नियुक्ति उनके पहले के रुख में एक बड़ा बदलाव है।

क्या है पूरा मामला?

ओशचाडबैंक और रूस द्वारा संयुक्त रूप से चुनी गईं जिमेनेज ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करेंगी, जबकि ब्रेकोलाकिस ओशचाडबैंक का और जस्टिस चंद्रचूड़ रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। कानूनी दल की बात करें तो, ओशचाडबैंक का प्रतिनिधित्व क्विन एमानुएल उर्कुहार्ट एंड सुलिवन के पार्टनर एपामिनोंटास ट्रायंटफिलो और एलेक्स गेर्बी के साथ एस्टर्स के पार्टनर ओलेक्सी डिडकोव्स्की, एंड्री पोझिदायेव और ओक्साना लेगा कर रहे हैं। वहीं, रूस का प्रतिनिधित्व पिन्ना गोल्डबर्ग के पार्टनर एंड्रिया पिन्ना, वकील प्रत्यूष पंजवानी और सीनियर एसोसिएट दिमित्रियोस पापाजॉर्जियो कर रहे हैं। यह मामला यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाइयों और रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में यूक्रेनी व्यवसायों व संपत्तियों को हुए नुकसान से उत्पन्न निवेश विवादों की व्यापक पृष्ठभूमि के बीच सामने आया है।

असम में बाढ़: एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, नदियां उफान पर, सीएम बोले- पुनर्वास के लिए एक हजार करोड़ की जरूरत

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

असम में बुधवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। चार जिलों में 1.12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और पहले से ही बाढ़ की चपेट में आए कई क्षेत्रों में और अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के एक अधिकारी ने बताया कि कई नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं, जिससे नए क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि आईएमडी के गुवाहाटी केंद्र ने चराइदेव, डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया जिलों के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ-साथ गरज और बारिश और मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। एएसडीएमए के दैनिक बाढ़ बुलेटिन के अनुसार, किसी नई मौत की सूचना नहीं मिली है और इस वर्ष की बाढ़ में मरने वालों की संख्या 101 पर बनी हुई है। बुलेटिन में कहा गया है कि गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर जिलों में बाढ़ से वर्तमान में 1,12,700 से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है, जहां 65,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, इसके बाद शिवसागर में लगभग 20,000 और नागांव में 16,000 से अधिक लोग बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। प्रशासन पांच जिलों में 92 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चला रहा है, जो 30,205 प्रभावित लोगों को सहायता कर रहे हैं। प्राधिकरण ने बताया कि राज्य भर में कम से कम 441 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 10,879.03 हेक्टेयर फसल भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है। बाढ़ के पानी ने कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है। एएसडीएमए के अनुसार, बाढ़ से राज्य भर में 31,650 घरेलू पशु और मुर्गी पालन प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि बाढ़ की ताजा लहर से तबाह हुए जिलों में संपत्तियों की मरम्मत और बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्वास प्रक्रिया में पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। सरमा ने कहा कि स्थायी राहत प्रदान करने के लिए, 9 अगस्त को राहत आकलन अभियान शुरू किया गया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, 8,000 से अधिक परिवारों का आकलन किया जा चुका है और 150 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह सर्वेक्षण 30 अगस्त तक जारी रहेगा और इसमें हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित ऊपरी जिलों के 50,000-60,000 परिवारों को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

पूर्व पीएम इमरान की सेहत को लेकर बड़ी चिंता, कस्टडी में मौत की अटकलों के बीच पार्टी ने की मांग

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा इस्लामाबाद

रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही है। इमरान खान की पार्टी और उनके परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि इमरान खान को हिरासत में रहते हुए जान का खतरा है। इमरान खान की बहन डॉ. उजमा ने कहा है कि उनके भाई ने उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर जेल में उन पर जानलेवा हमला होता है तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। 73 वर्षीय इमरान खान साल 2023 से पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी पीटीआई बार-बार आरोप लगा रही है कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही जेल में इमरान खान को सही चिकित्सा देखभाल मिल रही है, जिससे उनकी हालत दिनों-दिन बिगड़ रही है। पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि जेल में इमरान खान की आंखों की रोशनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इमरान खान की पार्टी के नेता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाता है तो हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच सकते हैं, जहां इमरान खान के शांति की अपील करने के बावजूद शांति कायम नहीं हो सकेगी। सोहैल अफरीदी ने चेताया कि 'वे युवा लोगों की आंखों में क्रांति की ज्वाला देख रहे हैं और अगर इसे अभी नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर इसे कोई नहीं रोक पाएगा।'

तिब्बत को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला: सीनेट में पेश किया नया विधेयक

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा वाशिंगटन

अमेरिकी सीनेट ने तिब्बत के भविष्य को सुनिश्चित करने वाला अधिनियम (एएफटीए) पेश किया है। इसका उद्देश्य तिब्बती लोगों और उनके लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व के साथ वाशिंगटन की भागीदारी को मजबूत करना है। इसके साथ ही उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करना है। सीनेटर जेफ मर्कले (डी-ओआर) और जिम रिस्क (आर-आईडी) की ओर से पेश किए गए इस विधेयक को सीनेटर टिम केन (डी-वीए), टॉड यंग (आर-आईएन), जैकी रोसेन (डी-एनवी) और रिक स्कॉट (आर-एफएल) ने सह-प्रायोजित किया है। सीनेट का विधेयक तिब्बत के भविष्य को सुनिश्चित करने वाले अधिनियम का पूरक विधेयक है। तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान के कार्यकारी निदेशक रयान फायरेसी ने विधेयक पेश किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि तिब्बती लोगों को अपने भविष्य का निर्धारण करने में अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत इस विधेयक को जल्द पारित कराने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। यह विधेयक एक मूलभूत सिद्धांत को मान्यता देता है कि तिब्बती लोगों को खुद अपने भविष्य का निर्णय करना चाहिए। 'अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट' के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति तिब्बती लोगों के साथ सीधे और उनके लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व के माध्यम से संपर्क बनाए रखना अनिवार्य होगा। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तिब्बती लोगों के मौलिक और मानवाधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग का समर्थन करता है, जिसमें आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल है। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन दलाई लामा की ओर से स्थापित तिब्बती लोगों के शासन की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने आगे कहा, 'यह विधेयक इस बात की पुष्टि करता है कि तिब्बत और चीन के बीच विवाद का समाधान करना संयुक्त राज्य अमेरिका के रणनीतिक हित में है। फायरेसी ने कहा, 'यह अमेरिकी सरकार को निर्देश देता है कि वह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ-साथ अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय निकायों में सीटीए को पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने के लिए पैरवी करे।

राज्यसभा सांसद को 'लुंगी वाला' कहा गया, सभापति हुए नाराज; दी सांसदों को सख्त हिदायत

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

राज्यसभा में बुधवार को सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि एक सदस्य द्वारा उन्हें 'लुंगी वाला' कहा गया। उन्होंने ऐसा कहे जाने पर आपत्ति जताई और इसे सदन की गरिमा और सम्मान से जोड़ा। जॉन ब्रिटास ने कहा, 'भारी मन से मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं, क्योंकि यह इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान का सवाल है। यह किसी एक दल का नहीं, बल्कि सभी दलों से जुड़ा मुद्दा है।' उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय, दक्षिण भारतीय और निश्चित रूप से एक गर्वित मलयाली हूं। इस पर सभापति ने टोकते हुए कहा कि कोई दक्षिण भारतीय या उत्तर भारतीय नहीं होता, हम सभी सिर्फ भारतीय हैं। ब्रिटास ने अपनी भाषा, संस्कृति और खान-पान व पहनावे पर गर्व जताते हुए कहा कि भारतीय संविधान देश की विविधता का सम्मान करता है। उन्होंने कहा, 'अगर आप मुझसे पूछें कि जब मैं इस सदन से विदा होऊंगा, जो बहुत जल्द हो सकता है, तो इस सदन से मेरी सबसे बड़ी सीख क्या होगी, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वह विविधता होगी। यही विविधता इस देश की एकता को एक अनूठे तरीके से कायम रखती है।' उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक ऐसी सदस्य, जिनका वह बहुत सम्मान करते हैं, उस समय उन्हें परेशान कर रही थीं, जब वह वैधानिक प्रस्ताव के प्रस्तावक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। ब्रिटास ने आरोप लगाया और कहा, 'हम एक-दूसरे से बहस कर सकते हैं, मौखिक तकरार भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने बार-बार मुझे 'लुंगी वाला, लुंगी वाला' कहकर संबोधित किया।' इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से कहा कि संबंधित सदस्य को बुलाकर दोनों पक्षों को सुना जाए और उसके बाद सभापति जो उचित समझें, उस पर निर्णय लें। रिजिजू ने सभापति से कहा, 'आप संबंधित माननीय सदस्य को बुला सकते हैं और उनकी बात भी सुन सकते हैं। इसके बाद आप जो निर्णय उचित समझें, वह ले सकते हैं।' सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों को नसीहत दी कि वे एक-दूसरे की भावनाओं और संवेदनाओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि सदन में सदस्यों द्वारा भाषण के दौरान असम्मानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां किए जाने के कई मामले उनके संज्ञान में आए हैं। सभापति ने कहा, 'माननीय सदस्यों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वे साथी सदस्यों की भावनाओं और संवेदनाओं को ठेस न पहुंचाएं। हमारी संस्कृति अनूठी है

19 राज्यों के 181 जिलों में खिसक रही जमीन

7500 जगह भूस्खलन का खतरा, क्या विकास की कीमत चुका रहे पहाड़ी इलाके?

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

देश के पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन का खतरा लगातार गंभीर बना हुआ है। देश के 19 राज्यों के 181 जिलों में करीब 7,500 ऐसी जगहें चिन्हित हैं, जहां जमीन खिसकने का खतरा बेहद ज्यादा है। हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। खतरा सिर्फ आम आबादी तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों, परिवहन गलियारों, सामरिक अवसंरचना और रक्षा प्रतिष्ठानों पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4.3 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को भूस्खलन संभावित क्षेत्र में शामिल किया है। हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर के राज्य और पश्चिमी घाट भूस्खलन के लिहाज से सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगातार जमीन खिसकने की घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसका असर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ वहां मौजूद सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर भी पड़ सकता है। रक्षा भू-सूचना अनुसंधान प्रतिष्ठान इन क्षेत्रों में जोखिम का आकलन कर रहा है और समय रहते चेतावनी देने के लिए तंत्र विकसित किया गया है। संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में अंधाधुंध निर्माण को जमीन खिसकने की बड़ी वजह माना गया है। पहाड़ों पर सड़कों, इमारतों और दूसरी परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक ढलानों से छेड़छाड़ होती है। पेड़ों की कटाई भी मिट्टी को कमजोर करती है। बारिश के दौरान यह खतरा और बढ़ जाता है। कई बार पहाड़ का हिस्सा खिसककर सीधे सड़क पर आ जाता है। जबकि कुछ जगहों पर सड़क का हिस्सा ही जमीन के साथ नीचे खिसक जाता है। इससे यातायात बाधित होने के साथ लोगों की जान और जरूरी ढांचे को नुकसान का खतरा बढ़ता है। आपदा प्रबंधन पर गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की 261वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन से महत्वपूर्ण अवसंरचना और परिवहन गलियारों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इससे निपटने के लिए हिम सुरक्षा सुरंग, छतनुमा सुरक्षा कवच, रिटेनिंग वॉल, अवरोध बांध और हिमस्खलन अवरोध टीले तैयार किए जा रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संदीप कुमार के लिए कसाणा प्रिंटिंग प्रेस, नियर बस स्टैंड भिण्डुसी, तहसील- तिजारा, जिला- अलवर (राजस्थान) पिन कोड- 301405, से मुद्रित तथा 109, धर्मशाला के पास, वीपीओ- हींगवाहेड़ा, तहसील- तिजारा, जिला- अलवर (राजस्थान) पिन कोड- 301411 से प्रकाशित। संपादक, संदीप कुमार Mob- 9414508610 E-mail:- pratigya.alwar@gmail.com पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के लिए जिम्मेदार, समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र अलवर होगा